

युवा सपनों को ऊंची उड़ान



2.2 लाख स्टार्टअप से युवाओं को रोजगार और नवाचार के अवसर

10,000+ अटल टिकिंग लैक्स से 1.1+ करोड़ छात्र विज्ञान और तकनीक से जुड़े

12 विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

श्री विष्णु देव साय
राज्य प्रमुख, अखिल

S 48144

छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए बिछा रेड कार्पेट, 9,580 करोड़ रुपये के मिले प्रस्ताव

रायपुर/हैदराबाद(प्रतिदिन राजधानी)

इन्वेस्टर कनेक्ट में हैदराबाद के निवेशकों को मुख्यमंत्री साय का निमंत्रण



छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए 'रेड कार्पेट' बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवानंन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली,

मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों

में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और करोड़ों रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों

एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गो सुविधाओं तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योगों के लिए इसे अत्यंत अनुकूल बनाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख पावर हब के रूप में उभर रहा है।

एएआईबी ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच पर जारी किया अंतरिम बयान

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 से संबंधित दुर्घटना की जांच पर अंतरिम वक्तव्य

एजेंसी, नई दिल्ली

विमान दुर्घटना की जांच करने वाली एजेंसी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने शुक्रवार को एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 से संबंधित दुर्घटना की जांच की प्रगति पर अपना अंतरिम वक्तव्य जारी किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि एएआईबी ने कहा है कि पिछले साल गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट, जांच से जुड़ी सभी गतिविधियों, जरूरी अंतरराष्ट्रीय समीक्षा और परामर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि एक वर्ष पहले एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट



(अहमदाबाद) से उड़ान भरने के तुरंत बाद 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार लोगों और जमीन पर मौजूद 19 लोगों सहित कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। एजेंसी ने कहा कि एयर इंडिया के बोइंग 787-8 स्लीमलाइनर विमान हादसे की पहली बरसी पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने कहा कि विमान प्रणालियों, फ्लाइट रिकॉर्डर के आंकड़ों, इंजन से जुड़े कल-पुर्जों, रखरखाव और परिचालन रिकॉर्ड समेत अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

एएआईबी ने इस दुखद दुर्घटना की बरसी पर कहा कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हम इस दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के असहनीय दर्द और पीड़ा को समझते हैं। एएआईबी संशोधित विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 और आईसीएओ अनुलग्नक 13 में निहित मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार जांच कर रहा है। इससे पहले विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने तथ्यात्मक जानकारी वाली एक प्रारंभिक रिपोर्ट 12 जुलाई 2025 को जारी की गई थी।

मोदी सरकार के 12 वर्ष विकसित भारत की मजबूत नींव के स्वर्णिम वर्ष : जेपी नड्डा

शिमला। केन्द्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अवधि केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्षों का प्रतीक है। भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के अभियान के तहत शुक्रवार को शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा और संस्कृति दोनों को बदला है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार तक सीमित थी, लेकिन मोदी सरकार ने राजनीति को सेवा, सुशासन और जवाबदेही का माध्यम बनाया है।

भाजपा ने भारतीय राजनीति में भरोसे के संकट को किया दूर : राजनाथ सिंह

एजेंसी, हैदराबाद
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सिकंदराबाद में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है और यदि भारतीय राजनीति में भरोसे के संकट को किसी दल ने दूर किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है। हाल के चुनावों में जनता ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जिन्होंने उसका विश्वास तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट नीति अपनाई है और यह तय किया गया है कि न तो सरकार भ्रष्टाचार करेगी और न ही किसी को करने दिया जाएगा।

कांकेर में आकाशीय बिजली गिरने से उपसरपंच सहित तीन की मौत, पांच घायल

कांकेर (प्रतिदिन राजधानी)

कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में आज शुक्रवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक उप-सरपंच सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कलगांव में आज सुबह मनरेगा में काम करने के दौरान हुई बारिश से बचने के लिए ग्रामीण पेड़ के नीचे आ गए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक उप-सरपंच सहित तीन लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में संतोष पटेल, प्रकाश



पटेल, मनराज पटेल (उपसरपंच) सभी कलगांव के निवासी हैं। सभी के शव को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया है।

अंतागढ़ पुलिस के अनुसार ग्राम कलगांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरी करण का कार्य किया जा रहा था। सभी ग्रामीण काम में लगे हुए थे। यहाँ पर करीब 70 ग्रामीण काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ बारिश

होने लगी, बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर पास के पेड़ के नीचे आ गये। तभी आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आठ लोग आ गए। इसमें तीन पुरुषों की मौत हो गई और पांच महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराया गया। एक महिला को जिसकी हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिये कांकेर रेफर किया गया है।

ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित हमले रोके समझौते के करीब पहुंचने का दावा

वॉशिंगटन (प्रतिदिन राजधानी)

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमलों और बमबारी को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच चुकी है और समझौते के कई प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनने की दिशा में प्रगति हुई है।

सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर जारी अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई चर्चाओं के बाद उन्होंने नियोजित सैन्य कार्रवाई रद्द करने का निर्णय लिया। उनके अनुसार, समझौते की रूपरेखा और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबंधित पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में अमेरिका के अलावा



इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्किये, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और मिश्र सहित कई देशों की भूमिका रही है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में लागू नौसैनिक नाकाबंदी फिलहाल जारी रहेगी और अंतिम समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने तक इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि समझौते से जुड़ी अगली घोषणाएं जल्द की जा सकती हैं।

इस बीच, अमेरिकी सैन्य कमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड

ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर महत्वपूर्ण दावा किया है। सेंटकॉम के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है और वहां सुरक्षित समुद्री मार्ग उपलब्ध है। सेंटकॉम ने कहा कि जो जहाज ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वे सामान्य रूप से इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि पिछले दो महीनों के दौरान सैकड़ों वाणिज्यिक जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरे हैं।

KALINGA UNIVERSITY

THE NEXT STEP TOWARDS EXCELLENCE.

The Journey Beyond Class 12 Begins Here.

Complete your application today!

PROGRAMS

PHARMACY
D.Pharmacy
B.Pharmacy
Pharm.D

COMMERCE & MANAGEMENT
B.Com.
B.Com. Hons.
(Banking & Finance)
{Includes GST & Taxation}
BBA

SCIENCE
B.Sc.

ARTS & HUMANITIES
BA | BA (J & MC) | BSW
BA (Lib. Arts)

DESIGN
Bachelor of Fashion Design
Bachelor of Interior Design

YOGA
Diploma
B.Sc.

LAW
BA LLB | BBA LLB

ENGINEERING
Diploma
B.Tech

INFORMATION TECHNOLOGY
DCA



Scan the QR CODE To Register for our Entrance Examinations
KALSEE/KAL-MAT

+91-9907252100

Campus: Kalinga University, Kotni, Near Mantralaya, Naya Raipur - 492101, Chhattisgarh
City Office: 2nd Floor, Aditya Heights, Opp. Telibandha Talab, Raipur - 492001, Chhattisgarh
Bhilai Office: 111, Khichariya Complex, Opp. Domino's Pizza, Near Hotel Grand Dhilon, Bhilai

REGISTER TODAY!

#KALINGA

कोंडागांव और दंतेवाड़ा की कार्यपालन अभियंताओं से मांगा गया स्पष्टीकरण, बस्तर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम से हुई थी शिकायत

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

जल जीवन मिशन के तहत संचालित नल जल योजनाओं से पानी नहीं मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने कोंडागांव और दंतेवाड़ा के कार्यपालन अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के हाल ही में बस्तर प्रवास के दौरान कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा तथा दंतेवाड़ा जिले के टेकरनार में जल अर्पण कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री से ग्रामीणों ने पानी नहीं आने की शिकायत की थी। इस पर श्री साव ने स्पष्टीकरण पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. मरकाम

ने कोंडागांव के कार्यपालन अभियंता वीरेन्द्र पाण्डेय से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए जारी नोटिस में कहा है कि विगत 5 जून को ग्राम बेड़मा, विकासखण्ड केशकाल, जिला कोंडागांव में उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव के प्रवास के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल अर्पण समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा गांववालों से नवनिर्मित योजना के संचालन-संधारण के संबंध में चर्चा के दौरान ग्रामवासियों ने शिकायत की थी कि योजना के सुचारु रूप से कार्यरत नहीं होने के कारण नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है एवं योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

विभाग ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान

नवनिर्मित योजना से जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत को गंभीर मानते हुए कार्यपालन अभियंता को



शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने व गुणवत्तापरक कार्य संपादन नहीं होना माना है। कार्यपालन अभियंता की कार्यप्रणाली से तत्समय अप्रिय एवं असहज स्थिति निर्मित हुई, जिससे विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव

पड़ा है।

प्रमुख अभियंता ने दंतेवाड़ा के कार्यपालन अभियंता एस.पी. मण्डवी को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए जारी नोटिस में कहा है कि विगत 7 जून को दंतेवाड़ा जिले के ग्राम टेकरनार में उप मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान आयोजित जल अर्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित नल जल योजना के संचालन-संधारण के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि योजना के सुचारु रूप से कार्यरत नहीं होने के कारण गांव के एक मोहल्ले के कुछ घरों में जलापूर्ति नहीं हो रही है जिससे मोहल्लेवासियों को योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रमुख अभियंता ने नोटिस में कहा है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान

नवनिर्मित योजना से समग्र रूप से तकनीकी रूपांकन अनुसार जलापूर्ति नहीं होना कार्यों के तकनीकी मापदण्ड अनुसार क्रियान्वयन नहीं किया जाना दर्शाता है। कार्यपालन अभियंता की कार्यप्रणाली से तत्समय अप्रिय एवं असहज स्थिति निर्मित हुई, जिससे विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने दोनों कार्यपालन अभियंताओं से 7 दिनों में अपना स्पष्टीकरण उचित माध्यम से प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करने को कहा है। स्पष्टीकरण विलंब से या प्राप्त नहीं होने की स्थिति में या समाधान कारक न होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

यातायात व्यवस्थाओं में सुधार एवं सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम को लेकर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न



रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

जिले में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर सभाकक्ष में बुधवार 10 जून को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी। कलेक्टर अभिजित सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी शामिल हुए। बैठक के प्रारंभ में विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन की विभागवार समीक्षा की गयी। जिसमें अधिकारियों ने कार्य पूर्ण होने, अद्यतन प्रगति एवं की गयी विभागीय कार्यवाहियों की जानकारी दी। साथ ही जिले की सड़कों में

यातायात सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। कलेक्टर श्री सिंह ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार अधिकारियों को सौंपे गए विभागीय कार्य, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर एवं स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचआई, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाना, लोक निर्माण विभाग (म./स. एवं वि./या.) को दुर्घटनाजन्य स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र बाहनों के लिए भारतमाला सड़क से जोड़ने, भारतमाला सड़क पर पुरई के पास बोगदा की हाइट बढ़ाने, भिलाई में केनाल रोड निर्माण तथा बारिश के पूर्व सभी अण्डरड्रिजों की सफाई एवं आवश्यक मरम्मत पर भी चर्चा की गयी। बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, एसपी यातायात श्रमा मिश्रा, नगर निगम आयुक्त भिलाई राजीव पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त दुर्ग सुमीत अग्रवाल, एसडीएम दुर्ग हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम भिलाई/भिलाई-03 महेश राजपुत, एसडीएम धमधा सोनल डेविड सहित लोक निर्माण विभाग, परिवहन, विद्युत विभाग, एनएचआई, एनएचआई, पुलिस विभाग और बीएसपी के अधिकारीगण उपस्थित थे।

महतारी वंदन की ई-केवाईसी में और तेजी

अब घर-घर पहुंचकर कराया जा रहा ई-केवाईसी

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

महतारी वंदन योजना के तहत शेष पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिए जिले में विशेष घर-घर अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) तथा वीएलई की संयुक्त टीम उन महिलाओं के घर पहुंच रही है जो वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता अथवा अन्य कारणों से स्वयं ई-केवाईसी केन्द्रों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। अभियान के तहत सेक्टरवार एवं ग्रामवार ऐसे हितग्राहियों की सूची तैयार की गई है जिनका ई-केवाईसी अभी शेष है। इन महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अमला घर-घर जाकर दस्तावेज सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इससे पात्र हितग्राहियों को सुविधा मिल रही है तथा किसी भी महिला के योजना से वंचित रहने की संभावना समाप्त हो रही है। इसी क्रम में रानीसागर खड़ियापाड़ा क्षेत्र में भी टीम द्वारा विशेष अभियान



चलाया गया। यहां तीन अस्वस्थ महिलाओं के घर वीएलई को लेकर पहुंची टीम ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया संपन्न कराई। जिसमें दो हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, जबकि एक प्रकरण में तकनीकी कारणों से प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी, जिसके निराकरण की कार्यवाही जारी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के ई-केवाईसी अभियान में रायगढ़ जिले ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य स्तरीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले ने 96.47

प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करते हुए सभी 33 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन की सतत समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय तथा मैदानी अमले के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता सिधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे तथा भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे, इसके लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में विशेष अभियान संचालित

किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सेक्टरवार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में लगभग 97 प्रतिशत हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है। शेष लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी तथा वीएलई लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग और अस्वस्थ महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनके घर पहुंचकर ई-केवाईसी कराया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अभियान के अंतिम चरण में शेष लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही का ई-केवाईसी पूर्ण कर रायगढ़ जिले को शत-प्रतिशत उपलब्धि की श्रेणी में लाया जाए। प्रशासन का लक्ष्य है कि महतारी वंदन योजना का लाभ जिले की सभी पात्र महिलाओं तक निर्बाध रूप से पहुंचे और कोई भी हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे।

अंतर्राष्ट्रीय फाटक दिवस के अवसर पर चलाया सघन जागरूकता अभियान



रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर दिनांक 06.06.26 से 12.06.26 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग के द्वारा समपार फाटक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 10.06.26 को संरक्षा अधिकारियों, संरक्षा सलाहकारों सिविल डिफेंस बोर्लैटियर एवं स्काउट गार्ड के द्वारा विभिन्न समपार फाटकों जैसे बालोद यार्ड गेट (समपार फाटक—59), कुसुमकसा गेट (समपार फाटक—59), लीमाटोला गेट(समपार फाटक—62), बोडताला गेट (समपार फाटक—386), सिधबाबा गेट (समपार फाटक 385), मातादेवालय गेट भाटापारा तथा लाटाबोर, कुसुमकसा, दल्लीराजहरा, तिल्दा एवं भाटापारा स्टेशन तथा भाटापारा मार्केट एरिया एवं पेट्रोल पंप तथा ट्रेन क्रमांक- 78815, 68861, 68862 एवं बिलासपुर-रायपुर लॉकल ट्रेन में जाकर लोगों को पॉम्पलेट वितरण करके, स्टीकर चिपका कर एवं बैनर लगाकर लोगों को फाटक बंद होने पर उसे पार न करने की काउंसिलिंग की गई।

समपार फाटक को सही तरीके से पार करने एवं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए कुल लगभग 1530 लोगों को काउंसिलिंग की गई। साथ में रायपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिनांक 10/06/26 को संरक्षा सलाहकारों तथा नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों, संरक्षा विभाग के द्वारा पाम्पलेट बाँटकर, स्लोगन व माईक के माध्यम से राहगीरों को जागृत किया गया। साथ ही समपार फाटक पार करते समय गाड़ी को धीमा चलाने, सिग्नल हरा होने पर ही आगे बढ़ने, फाटक बंद हो तो खुलने का इंतजार करने तथा फाटक पार करते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने का परामर्श दिया गया।

रायपुर नगर पालिक निगम

आयुक्त संबित मिश्रा ने प्रतिदिन 1 करोड़ रूपये का राजस्व वसूलने का पुनः लक्ष्य दिया

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने रायपुर नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में साप्ताहिक टीएल समयासीमा की बैठक लेकर विभिन्न विषयों पर कार्यों की समीक्षा कर सम्बंधित निगम अधिकारियों को आवश्यक साप्ताहिक टी एल समयासीमा की बैठक में नगर निगम अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, श्रीमती कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता संजय बागड़े, अधीक्षण अभियंता



राजेश राठौर, इमरान खान, प्रदीप यादव, जॉन कमिश्नरों, उपायुक्तगणों, कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं की उपस्थिति रही। आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जॉन कमिश्नरों को नगर निगम रायपुर के सभी बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर उनसे सम्पूर्ण बकाया राजस्व वसूलने नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के पुनः

निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने सभी 10 जॉनों को मिलाकर प्रतिदिन एक करोड़ रूपये का राजस्व वसूलने का लक्ष्य पुनः निर्धारित कर इसका निगम हित में कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया है। आयुक्त संबित मिश्रा ने दिनांक 30 जून 2026 तक सम्पत्तिकर की वर्ष 2026-27 हेतु पूर्ण अदायगी किये जाने पर सम्बंधित सम्पत्ति करदाताओं

को नियमानुसार 6.25 प्रतिशत की सम्पत्तिकर में छूट का पूर्ण लाभ प्रदान करते हुए अधिकाधिक राजस्व वसूलने नगर निगम हित में करने के सख्त निर्देश पुनः सभी जॉन कमिश्नरों को दिए हैं।

आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जॉन कमिश्नरों को रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्डों में समस्त अवैध नल कनेक्शनधारकों को कनेक्शन को निरामित नहीं करवाने की स्थिति में धारकों पर नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश सभी जॉन कमिश्नरों को दिए हैं।

आज रायपुर नगर पालिक निगम जॉन क्रमांक 2 स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त स्वच्छता से सम्बंधित जनशिकायत को तत्काल सज्ञान में लेकर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देश पर नगर निगम जॉन 2 जॉन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय के मार्गनिर्देशन एवं जॉन 2 जॉन स्वास्थ्य अधिकारी श्री रवि लावनिया की उपस्थिति में नगर निगम जॉन 2 क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा गाँधी वार्ड क्रमांक 27 क्षेत्र के अंतर्गत केलकरपारा स्टेशन रोड में स्थल पर पहुंचकर सफाई करवाकर कचरा तत्काल उठवाकर स्वच्छता कायम की जाकर इस सम्बन्ध में प्राप्त जनशिकायत का जॉन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया।



आज रायपुर नगर पालिक निगम जॉन क्रमांक 2 स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त स्वच्छता से सम्बंधित जनशिकायत को तत्काल सज्ञान में लेकर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देश पर नगर निगम जॉन 2 जॉन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय के मार्गनिर्देशन एवं जॉन 2 जॉन स्वास्थ्य अधिकारी श्री रवि लावनिया की उपस्थिति में नगर निगम जॉन 2 क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा गाँधी वार्ड क्रमांक 27 क्षेत्र के अंतर्गत केलकरपारा स्टेशन रोड में स्थल पर पहुंचकर सफाई करवाकर कचरा तत्काल उठवाकर स्वच्छता कायम की जाकर इस सम्बन्ध में प्राप्त जनशिकायत का जॉन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया।

वृन्दावन कॉलोनी रायपुरा में 1-1 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बिना अनुमति निर्मित दो भवन/मकान तोड़े गए

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जॉन 8 जॉन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता श्री अमन चंद्राकर, अनुराग पाटकर, उप अभियंता श्री लोचन चौहान, श्री अबरार खान एवं नगर निवेश विभाग टीम की उपस्थिति में नगर निगम जॉन 8 क्षेत्र अंतर्गत संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा डुस्सा तलाब के पास लगभग 1100 वर्गफीट क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की गयी। इसके साथ ही इन्द्रप्रस्थ



कालोनी के पास स्थित वृन्दावन कॉलोनी रायपुरा में लगभग 1000-1000 वर्गफीट पर बिना अनुमति के 2 भवन/मकान बनाये गए थे, जिसे तोड़ने की स्थल पर कार्यवाही की गयी। इसके विभिन्न स्थानों में सी एंड

डी वेस्ट मिलने पर सड़क बाधा शुल्क एवं बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य करने को लेकर कार्यवाही करते हुए सम्बंधितों पर ई चालान कार्यवाही करते हुए कुल 7000 रूपये की वसूली की कार्यवाही की गयी।

कांक्रिट और ट्री गार्ड के घेरे को हटाने का अभियान प्रारम्भ

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और छत्तीसगढ़ शासन के समाजहितकारी निर्देश पर रायपुर जिला प्रशासन द्वारा रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के मार्गनिर्देशन में ऐसे सभी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने और पानी प्राप्त करने देने हेतु चारों



ओर से कांक्रिट और ट्री गार्ड से घिरे हुए समस्त पौधों को प्राकृतिक विकास हेतु पानी प्राप्त करने देने पर्यावरण में रायपुर जिला प्रशासन के पुनर्जीवन के अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने नगर निगम के सभी जॉन कमिश्नरों को अपने-अपने जॉन क्षेत्र के सभी वार्डों में चारों ओर से

कांक्रिट के घेरे और ट्री गार्ड आदि से घिरे हुए समस्त पौधों को चारों ओर लगे हुए कांक्रिट और ट्री गार्ड के घेरों को अतिशीघ्र हटाकर उन्हें हेतु ऐसे सभी पौधों को पर्यावरण हितेषी वातावरण देने का कार्य समाजहित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पहली प्राथमिकता के आधार पर करने किया है।

निगम अपर आयुक्त ने सीएसईबी अधिकारियों जॉन कमिश्नरों की बैठक लेकर कार्य समीक्षा की

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय ने नगर निगम मुख्यालय भवन में मुख्य अभियंता श्री संजय बागड़े, कार्यपालन अभियंता विद्युत श्री सदीप शर्मा सहित सभी जॉन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं सहित सीएसईबी अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेकर समन्वय सहित विद्युत संबंधी समस्याओं का शीघ्र निदान करने के संबंध में निर्देश दिये। अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय ने



सीएसईबी अधिकारियों को रायपुर नगर निगम से संबंधित सपत्तिकर के छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को देय लगभग 15 करोड़ रु के देयको को बिजली बिल में समायोजन करने के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जॉन कमिश्नरों ने जॉनों के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों

पर जॉन 4 क्षेत्र में नेताजी सुभाष स्टेडियम एवं जॉन 9 क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक भवन सहित अन्य स्थानों पर विद्युत मीटर सबंधी समस्याओं की जानकारी दी। जिस पर अपर आयुक्त ने समन्वय कर शीघ्र समाधान किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिये।

सम्पादकीय

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

यू तो भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के तमाम दावे गाहे-बगाहे किए ही जाते हैं। आधी दुनिया को पूरा हक देने की बात होती है। किंतु परंतु के बीच उन्हें जनप्रतिनिधि संस्थाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने पर प्रतिबद्धता जतायी जाती है। लेकिन इन दावों के बीच सामने आया एक कड़वा सच हमें वास्तविक स्थिति से रूबरू करा देता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में ग्रामीण इलाकों में हर चौथी और शहरी क्षेत्र में हर छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती रही है। यह विडंबना ही है कि शहरों की तुलना में ज्यादा शांत व सुरक्षित माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों को घरेलू एवं यौन हिंसा का ज्यादा सामना करना पड़ता है। वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें नेशन बिल्डर तक कह दिया। यहां तक कि घर और परिवार की देखभाल में गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कल्पित आर्थिक मूल्य का निर्धारण करते हुए उसे नजरअंदाज न करने की इलाह दी। यह विडंबना ही है कि जिन महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने नेशन बिल्डर बताया है, उन्हें हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आखिर महिला सशक्तिकरण के सारे विशेष प्रयास सिर्फ कागजों तक ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि महिलाओं की रक्षा-सुरक्षा हेतु तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। इसमें दो राय नहीं कि समय-समय पर महिला उत्थान के लिये तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान चलाये जाते रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकासवात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जीवन के हर क्षेत्र में वे अपना आकाश तलाश रही हैं। विधायिका में तैत्तिस प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल सहमत नजर आते हैं। सवाल यही है कि जीवन व्यवहार में स्थिति क्यों नहीं बदलती। देश के नीति-निर्णयताओं को इस गंभीर मुद्दे पर विचार करना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में हर चौथी व शहरी क्षेत्र में हर छठी स्त्री को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि घर से लेकर बाहर तक वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं? क्या कहीं इसमें पिनुसता प्रधान समाज की मानसिकता कारण है? दरअसल, आज लड़कियों व महिलाओं के खिलाफ हिंसा कई रूपों में मौजूद है। आजादी के सात दशक बाद भी हम दहेज के कलंक से मुक्त नहीं हो पाये हैं। हाल के दिनों में दहेज हत्या के कई बहुचर्चित मामले प्रकाश में आए।

जेन-जी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान, सपनों में जी रहा

जेन-जी को ना तो वामपंथी विचारधारा पर विश्वास है ना ही उसे पूंजीवाद पर विश्वास है, वह पूरी तरह से सैल्फिश होकर केवल अपने बारे में सोचती है। उसे अपने परिवार और मां-बाप की कठिनाइयों से भी कोई सरोकार नहीं रहता है। वह जब भी बात करता है केवल अपने हित की बात करता है। वह अपने माता-पिता और परिवार से दूर रहकर केवल अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार से उतना ही जुड़ता है जो उसकी जरूरत पूरी करने के लिए जरूरी होती है।

सनत जैन

पूरी दुनिया में जेन-जी की आबादी चिंता का कारण बनती चली जा रही है। यह युवा आबादी ना तो अपने परिवार के बारे में सोचती है, नाही समाज के बारे में सोचती है, यह केवल अपने बारे में सोचती है। इसके पास शिक्षा की डिग्रियां भी हैं, लेकिन डिग्री के अनुरूप ज्ञान नहीं है। जीवन जीने का कोई अनुभव नहीं है। वह कोई चीज सीखना भी नहीं चाहते हैं। किसी चीज से जुड़ते हैं और उसे जल्दी ही छोड़ देते हैं। उनका सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बीत रहा है, जिसके कारण वह सामान्य ज्ञान से भी दूर होते चले जा रहे हैं। वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है वह डिग्री लेकर बड़े-बड़े सपने देखती है लेकिन डिग्री के अनुरूप उसके पास ना तो कोई ज्ञान होता है नाही वह कोई काम करना चाहता है जिसके कारण यह युवा पीढ़ी एक बड़ी चिंता का कारण भी बन रही है।

भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, यूरोपीय देश सभी में जेन-जी के इस बर्ताव से सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में अब एक तनाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट आफ

पॉलिटिक्स ने 2020 से 2025 के बीच जो सर्वे किया था उसमें यह बात खुलकर सामने आई कि इस युवा पीढ़ी को पूंजीवाद वामपंथ समाजवाद इत्यादि विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है। यह केवल अपनी जरूरत से जुड़कर ही अपनी बात रखता है। मेरा किराया कम करो, फीस माफ करो, मुफ्त बस सेवा दो, मुझे नौकरी दो, नौकरी भी सबसे अच्छी वाली चाहिए है, जिसमें बड़ा वेतन मिलता हो, कॉरपोरेट ऑफिस हो। इस तरह की मांग इस युवा पीढ़ी की होती है, लेकिन यह अनुभव प्राप्त करने के लिए अथवा जो भी नौकरी या रोजगार करना चाहता है जो उसके सपने में है उसके लिए वह अपने आपको तैयार भी नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए उसके सपने बड़े-बड़े हो गए हैं। सारी दुनिया में क्या हो रहा है यह उसे पता है लेकिन उसका करियर कैसे बनेगा इसके बारे में वह जरा भी गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि यह अपने मां-बाप को भी अपना नहीं मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वह उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वह उनसे भी नाराज रहकर विद्रोह करने की स्थिति में आ जाता है। वर्तमान में वह वर्ग बढ़ती हुई महंगाई,

बेरोजगारी तथा इसका रहन-सहन और खर्च करने की आदत के कारण यह सबसे ज्यादा परेशान है। हाल ही में जो सर्वे हुए हैं उनमें 36 फीसदी युवा इसी स्थिति से गुजर रही है। यह युवा वर्ग अरबपतियों पर भारी टैक्स लगाने का पक्षधर है। यह बाजारवाद का शिकार हो गया है। सारी दुनिया में जिस तरह से कॉरपोरेट लगातार सामान की कीमत बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उससे यह युवा वर्ग के टारगेट में आते चले जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी निर्वाचित हुए हैं, उनकी जीत में सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि उन्होंने जेन-जी के इस मनोविज्ञान को समझा उन्होंने इसी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा लोक लुभावन वायदे किए। ममदानी ने निम्न वर्ग और मध्य वर्ग को महंगाई से राहत दिलाने की बात की, उन्होंने महंगाई के खिलाफ सभी लोगों को एकजुट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बाद भी उन्होंने न्यूयॉर्क में मेयर के पद के चुनाव में जीत हासिल की। अब उनकी देखा-देखी यूरोप के अन्य देशों में भी चुनाव जीतने के लिए यही फार्मुला अपनाया जा रहा है। ब्रिटेन के ग्रीन पार्टी के नेता जैक पोलंसकी भी चुनाव जीतने के



लिए लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। भारत पर पिछले एक दशक से राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए इसी तरह के वादे करके चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत में जेन-जी की समस्याओं को हल करने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। इस दिशा में भी जेन-जी गंभीर नहीं नजर आता है। वैश्विक व्यापार संधि के बाद सारी दुनिया में कर्ज और बाजारवाद की जो आंधी चली है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित यही जेन-जी हुआ है। इसने अपने सपने पूरे करने के लिए एजुकेशन लोन भी लिया है। गाड़ी-घोड़े भी लोन से लिए हैं। मोबाइल फोन भी किस्तों पर लेकर तथा क्रेडिट कार्ड और अन्य तरीके से कर्ज लेकर अपने खर्च पूरे करने का जो तरीका अपनाया था वह उसकी

आदत में शुमार हो चुका है। जिस तरह से भारत सहित दुनिया के सभी देशों में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, रही सही कसर ए आई तकनीकी के कारण बेरोजगारी और तेजी के साथ बढ़ रही है। महंगाई भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या एक विकट रूप में सामने आ रही है। इस समस्या का समाधान किस तरह से होगा, इसको लेकर अब दुनिया भर के विश्वविद्यालय शोध कार्यक्रम चला रहे हैं। डिग्रियों के बावजूद जेब काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब कॉलेज और विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। हर साल बड़ी संख्या में सीट खाली रह जाती हैं। महंगाई के कारण मांग घटती चली जा रही है।

कारपोरेट जगत का मुनाफा निश्चित रूप से बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है लेकिन जिस तरह से अब मांग घटने लगी है इसके कारण कॉरपोरेट भी चिंतित नजर आने लगे हैं। बदली हुई इस व्यवस्था को लेकर सारी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। दुनिया में आर्थिक मंदी और महंगाई दोनों ही बढ़ रही हैं। जिस तेजी के साथ जेन-जी का गुस्सा देखने को मिलता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एवं अन्य देशों की घटनाओं को देखते हुए यह क्षणिक में बहुत बड़ा मुकाम पर देता है और उसके बाद निराशा में शांत होकर बैठ जाता है। इस वर्ग के इस आचरण को देखते हुए किसी क्रांतिकारी बदलाव की आशा भी देखने को नहीं मिल रही है। इससे सभी आश्चर्यचकित हैं।

विकसित भारत का मार्ग : नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक से निकला नया विकास मंत्र

विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'।



नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य की विकास दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विमर्श था। विकसित राज्य से विकसित भारत की थीम पर आयोजित इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने प्रदेशों की आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास संबंधी सुझावों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा। सर्वविधित रहे यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुकी है और अगले दशक में इसे 10 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में राज्यों की भागीदारी और उनकी विकास क्षमता निर्णायक महत्व रखती है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि विकसित भारत का सपना दिल्ली में बैठकर पूरा नहीं किया जा सकता इसके लिए राज्यों को विकास का इंजन बनना होगा। उन्होंने राज्यों से निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, कृषि आधुनिकीकरण, कौशल विकास और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा रखे

गए सुझाव और मांगें रहीं इन सुझावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्यों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, तेज, समावेशी और सतत विकास। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को कृषि एवं औद्योगिक हब बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं, लांजिस्टिक कॉरिडोर और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने केंद्र से अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग की मांग की। नवाब सिंह सैनी ने हरियाणा को विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए औद्योगिक गलियारों, कौशल विकास और एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कृषि में ड्रोन

तकनीक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया। भजन लाल शर्मा ने जल संकट को राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए नदी जोड़ो परियोजनाओं और जल संरक्षण कार्यक्रमों में केंद्र के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका को और मजबूत करने की बात कही। योगी आदिनारायण ने उत्तर प्रदेश के तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और डिफेंस कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए राज्यों को अधिक वित्तीय लचीलापन देने की मांग रखी ताकि विकास परियोजनाओं को गति मिल सके। देवदर फ़डनवीस ने मुंबई महानगर क्षेत्र, सेमीकंडक्टर उद्योग और हरित

ऊर्जा निवेश को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार बताते हुए वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों को अधिक नीति समर्थन देने की बात कही। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया। उनका मत था कि बेहतर संपर्क व्यवस्था ही क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय औद्योगिकता का आधार बनेगी। इस बैठक में कृषि क्षेत्र पर विशेष चर्चा हुई। आज भी लगभग 45 प्रतिशत भारतीय आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्यों ने प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि निर्यात और भंडारण सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। कई मुख्यमंत्रियों ने कृषि मूल्य श्रृंखला को

मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता बताई। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र भी चर्चा के केंद्र में रहे। राज्यों ने चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने, जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने तथा नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसलिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने पर व्यापक सहमति दिखाई दी। हरित ऊर्जा को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार सामने आए। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जोवाशम ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और

महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का भी उल्लेख हुआ। आज भारत में 150 करोड़ से अधिक आधार प्रामाणीकरण प्रतिमाह हो रहे हैं और यूपीआई लेन-देन विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क बन चुका है। राज्यों ने डिजिटल प्रशासन और सेवा विरण में कुत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों को अपनाने का सुझाव दिया। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सहकारी संघवाद की भावना का और अधिक मजबूत होना रहा। केंद्र और राज्यों के बीच संवाद, सहयोग और साझेदारी के माध्यम से विकास के नए मॉडल विकसित करने पर सहमति बनी। यह स्पष्ट हुआ कि विकसित भारत का मार्ग नीति से होकर ही गुजरता है।

निष्कर्षतः नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक ने केवल नीतिगत चर्चा नहीं की, बल्कि भारत के अगले दो दशकों के विकास का व्यापक खाका प्रस्तुत किया। मुख्य मंत्रियों के सुझावों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास दृष्टि ने यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत का विकास मॉडल अधिक वित्तीय, सहभाग्यी और परिणामोन्मुख होगा। यदि इस बैठक में सामने आया सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक सरकारी संकल्प नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक उपलब्धि बन सकता है।

ऐतिहासिक कार्यकाल, परिवर्तनकारी नेतृत्व....



भारत ने 10 जून, 2026 को अपने लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय दर्ज किया। इस रोज श्रीमान नरेंद्र मोदीजी ने प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचन सेवा के 4,399 दिन पूरे कर लिए। इसके साथ ही वह भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। यह ऐतिहासिक उपलब्धि सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को ही नहीं दिखाती। यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के लोगों के अडिग विश्वास और आस्था की भी प्रतिबिंबित करती है। यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रीय विकास के लिए अथक प्रतिबद्धता तथा भारत की अवागम के कल्याण और आकांक्षाओं प्रति अटूट निष्ठा को प्रतिबिंबित करती है।

परिवर्तन के युग की शुरुआत की है। इतिहास अब्राहम लिंकन को मानव दासता का अभिशाप खत्म कर लाखों लोगों की गरिमा बहाल करने में उनके अडिग नेतृत्व के लिए उनका आदर करता है। इसी तरह, आने वाली पीढ़ियों 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पूर्ण निर्धनता से बाहर निकालने के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदीजी को याद करेगी। उनकी दृष्टि, अथक प्रयासों और परिवर्तनकारी शासन ने अनगिनत परिवारों को अवसर, गरिमा और उम्मीद देकर सशक्त बनाया है तथा वे आर्थिक स्वतंत्रता और बेहतर भविष्य के आश्वासन को अपनाने में समर्थ बने हैं। उनका योगदान मानवता की सेवा में एक युगांतकारी उपलब्धि के रूप में इतिहास में दर्ज रहेगा। इतना ही नहीं, उनकी परिवर्तनकारी पहलकदमियों ने शिक्षा, आवासन, स्वच्छता, स्वास्थ्यसेवा और खाद्य निश्चितता के माध्यम से करोड़ों लोगों की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक, आयुष्मान भारत योजना के जरिए 44 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यसेवा प्रदान की गई है। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल पहुंचा कर अनगिनत परिवारों को गरिमा प्रदान की और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। निःशुल्क खाद्यान्न के 2020 से जारी प्रावधान से लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा की रक्षा होने के अलावा यह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी कमजोर नागरिक पीछे नहीं छोटे पाए। इसके अतिरिक्त, 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों का सुरक्षित और स्थाई घर का मालिक बनने का सपना पूरा हुआ जिससे उनमें सुरक्षा, गरिमा और भविष्य के लिए

उम्मीद की भावना मजबूत हुई है। कुल मिला कर, ये पहलकदमियां एक सहृदय शासन और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता के स्थाई प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण ने समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया है—चाहे वे महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों या वंचित वर्ग के लोग। 3 करोड़ से ज्यादा 'लक्ष्मि दीवियों' का सामने आना महिला नेतृत्व में विकास के उनके दृष्टिकोण का एक सशक्त प्रमाण है, जबकि 'नारी शक्ति' के तहत शुरू की गई पहलों ने महिलाओं को देश के निर्माण में और भी अहम भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है। नए आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना से भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है, जिससे देश के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हुए हैं। साथ ही, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति देखी है। वंदे भारत ट्रेनों, हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के तेजी से विस्तार से लेकर दूर-दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली परियोजनाओं तक, उनके नेतृत्व में एक आधुनिक, आपस में जुड़े हुए और महत्वाकांक्षी भारत की नींव रखी है। इन उपलब्धियों ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि देश भर के लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है। भारत डिजिटल नवाचार, सेमी-कंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वैक्सीन बनाने और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जिससे उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विश्व में हमारे देश की स्थिति और मजबूत हुई है।

विकास : समकालीन नेताओं में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बात सबसे अलग और अनूठी बनाती है, वह है उनका यह दृढ़ विश्वास कि विकास और परंपरा कोई परस्पर विरोधी विचार नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। 'विकास भी, विरासत भी' की अपनी दूरदर्शी सोच के जरिए उन्होंने यह दिखाया है कि कोई देश अपनी सभ्यतागत विरासत से जुड़े रहते हुए भी तेजी से आधुनिकीकरण की राह पर आगे बढ़ सकता है। उनके नेतृत्व में, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग और समाज कल्याण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास किया है और इसके साथ ही अपनी प्राचीन संस्कृति, भाषाओं, आध्यात्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत के प्रति एक नए गौरव की अनुभव किया है। चाहे पवित्र स्थलों का जीर्णोद्धार हो, सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुत्थान हो, शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना या अमूल्य कलाकृतियों का संरक्षण हो— उनके शासन में आधुनिक आकांक्षाओं और शाश्वत मूल्यों का दुर्लभ समन्वय देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नजरिए पर राष्ट्र-निर्माण की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा है। उन्होंने यह साबित किया है कि असली विकास का पैमाना सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं है, बल्कि इसे इस बात से भी मापा जाता है कि एक राष्ट्र अपनी विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने, संजोने और सौंपने में कितना सक्षम है। उनकी 'विकास भी, विरासत भी' की सोच एक ऐसे आत्मविश्वास से भरे और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते भारत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई है, जो अपने गौरवशाली अतीत से मजबूती से जुड़े रहते हुए भविष्य की ओर निडरता से कदम बढ़ा रहा है। इस सोच का सबसे ज्यादा फ़ायदा तमिलनाडु और दुनिया

भर में फैले तमिल समुदाय को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को अभूतपूर्व पहचान, सम्मान और समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही परिवर्तनकारी पहलों से तमिलनाडु को बहुत लाभ हुआ है, जिनमें एक-दो मेट्रो रेल का विस्तार, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और नया पायबन रेल पुल शामिल हैं। भारत के पहले वर्टिकल-लिफ्ट सी-ब्रिज, नए पायबन रेल पुल का उद्घाटन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो रामेश्वरम के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है और भारत को इंजीनियरिंग उद्युच्छता का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के निरंतर और दृढ़ प्रयास के कारण, तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र के तौर पर भी उभरा है। पूर्व के किसी भी प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा, संस्कृति और विरासत को उस निरंतरता, प्रमुखता और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा नहीं दिया जैसा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उन्होंने तमिल सभ्यता को एक नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। भारत और विदेशों में तमिल की प्राचीनता और साहित्यिक समृद्धि का उनके द्वारा लगातार किया गया गौरवगान दुनिया भर के तमिलों के दिलों को गहराई से छू गया है। इस गहरे संदेश को वैश्विक मंच पर लाकर, उन्होंने दुनिया को तमिल संस्कृति में निहित शाश्वत मानवीय मूल्यों और उसकी समृद्ध सभ्यतागत विरासत से परिचित कराया। मानवता को यह एहसास हुआ कि कार्ल मार्क्स से सदियों पहले ही

तमिलों ने 'एक मानवता' के नेक विचार को अपनाया था। 'वसुधैव कुटुंबकम्' की पहल भी इसी दर्शन पर आधारित है। 'काशी-तमिल संगमम्' और 'सौराष्ट्र-तमिल संगमम्' जैसी पहलों ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है और उन स्थायी सभ्यतागत रिश्तों को उजागर किया है जो हमारे देश को एकजुट करते हैं। हमारे नए संसद भवन में 'संगोल' की स्थापना, भारत की लोकतांत्रिक और सभ्यतागत विरासत में तमिलनाडु के योगदान की एक सटीक पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गंगाईकोंडा चोलपुरम की यात्रा चोल वंश की विरासत को उजागर करती है। साथ ही, विदेशों से बेशकीमती कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की व्यापक रूप से सराहना की गई है, इनमें हाल ही में अनार्इमंगलम से मिली चोल-युगान तबिके के ताम्रपत्र भी शामिल हैं। मंदिरों, धरोहर स्थलों, शास्त्रीय साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए उनके समर्थन के साथ-साथ, इन प्रयासों ने विश्व में तमिल सभ्यता की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है और तमिल भाषा व संस्कृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को भी दर्शाया है।

निष्कर्षतः हर दौर में इतिहास ऐसे नेताओं के उदय का गवाह रहा है, जिनकी सोच और काम उनके समय की सीमाओं से कहीं आगे होते हैं। ऐसे लोगों को 'युग पुरुष' के तौर पर याद किया जाता है क्योंकि वे देश की परियत बदलते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। अपने परिवर्तनकारी नेतृत्व, राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता और जनता की अथक सेवा के माध्यम से, वह समकालीन भारत के एक सबसे 'युग पुरुष' के रूप में उभरे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कुशल नेतृत्व राष्ट्र को 'विकसित भारत 2047' की ओर ले जाएगा।

फिल्में समाज को संदेश देने का सशक्त माध्यम- राज्यपाल डेका

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

फिल्में और डॉक्यूमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक संदेश देने का एक प्रभावी साधन हैं। राज्यपाल श्री रमेश डेका ने आज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में उक्त बातें कही। यह कार्यक्रम रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

राज्यपाल ने कहा कि आदिम युग से ही मनुष्य विभिन्न माध्यमों से अपने विचार और संदेश व्यक्त करता रहा है।



समय के साथ नाटक, रेडियो, टेलीविजन और अब डिजिटल माध्यमों ने इस भूमिका को और व्यापक बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले सिनेमा का मूल उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि समाज को संदेश देना और जागरूक करना था। स्वतंत्रता

आंदोलन के दौरान भी भारतीय सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध उल्लेखनीय सफलता मिली है। फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि अब वे बस्तर

की समृद्ध संस्कृति से देश और दुनिया को परिचित कराएं। इससे क्षेत्र की सकारात्मक छवि को मजबूती मिलेगी। राज्यपाल ने सद्गति, चरणदास चोर और देवदास जैसी फिल्मों और नाटकों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जागरूकता लाने वाली फिल्मों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और पर्व-त्योहारों जैसे हमारे धरोहर को स्थायी रूप से संरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। उन्होंने कलाकारों से लोककला, लोकगीत, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने

में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि मोबाइल की बढ़ती लत आज गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। बच्चे खेल के मैदानों से दूर हो रहे हैं और उनकी रचनात्मकता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कलाकारों से आग्रह किया कि वे नई पीढ़ी को कला, संगीत, नाटक और नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आगे आएं। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री फिल्मों छत्तीसगढ़ के भीम दाऊ चिंताराम, हैप्पी बर्थडे और स्क्रीन के निर्माता-निर्देशकों को सम्मानित किया।

16 जून से ही खुलेंगे स्कूल, शाला प्रवेश उत्सव 2026 को लेकर आदेश जारी

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

16 जून से ही स्कूल खुलेंगे। शाला प्रवेश उत्सव 2026 को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन की स्पष्ट मंशा है कि छात्र-छात्राओं को स्वच्छ व सुन्दर वातावरण में गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए। स्कूल शिक्षा विभाग इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इस वर्ष भी शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन 16 जून, 2026 से प्रत्येक स्तर पर किया जाना है। इस हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि शाला - प्रवेश उत्सव की प्रारंभिक तैयारी के साथ-साथ पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी किया जाए। शाला प्रवेश उत्सव हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें- 1. शाला प्रवेश उत्सव का जोर-शोर से एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे तथा यथासंभव बैनर-पोस्टर लगाया जावे, रैली निकाली जावे। गांवों में तथा वार्डों में मुनादी कराई जावे। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं शाला विकास समिति एवं को विशेष रूप से आमंत्रित किया जावे। 2. शाला प्रारंभ होने के पूर्व शाला भवन / परिसर /अध्यापन कक्षा की साफ-सफाई एवं मरम्मत कर ली जावे शाला को आकर्षक एवं परिसर में प्रिन्ट - रिच वातावरण बनाया जावे।

हौसलों की उड़ान संघर्षों को मात देकर लखपति दीदी बनीं कांति साहू

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर शलखपति दीदी बन रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसी कई महिलाओं ने प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं और छोटी पूंजी की मदद से स्वरोजगार अपनाकर अपनी तकदीर बदली है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत चल रहा लखपति दीदी अभियान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। इसका सबसे सटीक और जीवंत उदाहरण बनी हैं बैकुण्ठपुर विकासखंड के ग्राम तलावापारा की रहने वाली श्रीमती कांति साहू। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच कांति ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि आज वे गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं।

समूह से जुड़ाव और 4 लाख की वित्तीय मदद एक सामान्य कृषक परिवार से तालुक रखने वाली कांति साहू हमेशा से खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थीं, लेकिन पूंजी के अभाव में उनका यह सपना दबा हुआ था। करीब तीन साल पहले वह गांव की महिलाओं के साथ मिलकर शारदा महिला स्वयं

दोना-पतल से कारोबार शुरू कर चार व्यवसायों का कर रही हैं सफल संचालन



सहायता समूह से जुड़ीं। समूह में आने के बाद उन्हें बचत और व्यावसायिक बारीकियों की समझ मिली। इसके बाद बिहान योजना के तहत बैंक लिंकेज, एसबीईपी योजना और मुदा ऋण के माध्यम से उन्हें करीब 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इस पूंजी ने उनके सपनों को पंख दे दिए।

एक नहीं, शुरू किए कई व्यवसाय कांति दीदी ने जोखिम उठाते हुए किसी एक व्यवसाय पर निर्भर रहने के बजाय

विविधता को चुना। उन्होंने एक साथ कई आजीविका गतिविधियों की शुरुआत की। दोना-पतल निर्माण इकाई, धान कृषि बीज केंद्र, मैचिंग सेंटर (कपड़ा व्यवसाय), सिलाई केंद्र, पति का मिला मजबूत साथ कांति साहू बताती हैं कि इस पूरे सफर में उनके पति महेंद्र साहू हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। शुरुआती चुनौतियों को मात देने में पति-पत्नी की साझा मेहनत और समर्पण का बड़ा योगदान रहा।

सालाना आय 3 लाख के पार

आज कांति साहू के सभी व्यवसाय सफलतापूर्वक चल रहे हैं। वर्तमान में इन व्यवसायों से हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपये तक का टर्नओवर (कारोबार) हो रहा है, जिसमें से वे 30 से 35 हजार रुपये का शुद्ध मासिक लाभ कमा रही हैं। इस तरह उनकी वार्षिक शुद्ध आय 3 लाख रुपये से अधिक हो गई है, जिससे उन्होंने आधिकारिक तौर पर शलखपति दीदीश्रेणी में अपनी जगह बना ली है।

महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल

आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही कांति का सामाजिक आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज वे न केवल अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर रही हैं, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखा रही हैं। कांति साहू की यह सफलता साबित करती है कि यदि ग्रामीण महिलाओं को सही मार्गदर्शन, वित्तीय सहयोग और अवसर मिले, तो वे समाज में महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम कर सकती हैं।

सामुदायिक भवन और चौक निर्माण के लिए 34 लाख मंजूर

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर नगर पंचायत में सामुदायिक भवन तथा भगत सिंह चौक के निर्माण के लिए 34 लाख 10 हजार रुपये की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रतापपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-6 में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 23 लाख 77 हजार रुपये की मंजूरी दी है। विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक-9 में भगत सिंह चौक के निर्माण के लिए भी 10 लाख 33 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है।

कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए 80 लाख

के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अधोसंरचना मद से यह राशि मंजूर की गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सिमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।



स्वीकृत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जशपुर नगर पालिका में वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख रुपये की मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सिमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का विशेष अभियान

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को लेकर एक विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है। अभियान के दौरान अब तक लगभग 350 वाहनों की सघन जांच की जा चुकी है। नियमों की अनदेखी और विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर वाहन स्वामियों से 5.50 लाख रुपये का सघन शुल्क (जुर्माना) वसूल किया गया है। इसके साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है।

स्लीपर बसों पर विशेष नजर, हटाए जा रहे अवैध केविन

परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश ने राज्य के सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित यात्री बसों, विशेषकर स्लीपर कोच बसों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस विशेष अभियान के तहत मुख्य बिंदुओं पर रूप से कार्रवाई की जा रही है।

अवैध केविन और स्लाइडर हटाना

स्लीपर कोच बसों में चालक दल (वर्क) के लिए बनाए गए अनधिकृत विभाजन (पार्टीशन) और स्लीपर बर्थ में लगाए गए अवैध स्लाइडरों को मौके पर ही हटाया जा रहा है।

अग्निशमन व्यवस्था

सभी बसों में सुरक्षा के लिहाज से न्यूनतम 10 किलोग्राम क्षमता के अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जा रही है। बसों में जीपीएस (ब्लैक) की उपलब्धता और उसकी कार्यशीलता को परखा जा रहा है। साथ



ही, निर्धारित मानकों के विपरीत बनी श्वस बॉडीश के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

दस्तावेजों का सत्यापन

बसों के वैध पंजीयन, फिटनेस, परमिट और एआईएस-119 मानकों के अनुरूप निर्माण की गहनता से जांच की जा रही है।

लापरवाही बरतने वालों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई परिवहन आयुक्त ने सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा है कि निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान काटने, परमिट/लाइसेंस निलंबित करने जैसी कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। परिवहन आयुक्त ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सड़क पर प्रवर्तन कार्रवाई करने के साथ-साथ विभाग संवाद का रास्ता भी अपना रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय व जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा बस स्वामियों और संचालकों की बैठकें ली जा रही हैं। इन बैठकों में उन्हें तय नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत और समझाइश दी जा रही है।

बेरोजगारी से उद्यमिता तक का सफर



रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

दृढ़ इच्छाशक्ति, मेहनत और सरकारी योजनाओं का सही लाभ किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। बीजापुर जिले के उसुर विकासखंड के ग्राम मुरदण्ड निवासी राघवेंद्र चाण्डी इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमडी) की मदद से उन्होंने बेरोजगारी से निकलकर एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

संघर्षों से भरा था जीवन

कुछ पहले तक राघवेंद्र बेरोजगार थे। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। आर्थिक परेशानियों के कारण परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। वे रोजगार की तलाश में थे, लेकिन उचित मार्गदर्शन और आर्थिक

सहयोग नहीं मिलने से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा था।

इसी दौरान उन्होंने जिला उद्योग केंद्र, बीजापुर से संपर्क किया। वहां अधिकारियों और जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) ने उन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमडी) की मदद से उन्होंने बेरोजगारी से निकलकर एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

आवेदन किया। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें 13 लाख 1 हजार 400 रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ।

ऋण मिलने के बाद राघवेंद्र ने अपने गांव में राइस मिल और टोरा मिल स्थापित की।

बारिश से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए गांव-गांव पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं

अब तक लगभग तीन हजार कुओं का शुद्धिकरण किया जा चुका है

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

वर्षा ऋतु के आगमन के साथ संभावित जलजनित एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशभर में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बलरामपुर जिला में कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिला के गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी विकासखंडों में मितानिनों के सहयोग से जल स्रोतों के शुद्धिकरण का कार्य तेज किया गया है। अब तक लगभग तीन हजार कुओं का शुद्धिकरण किया जा चुका है, जबकि शेष जल स्रोतों में भी यह कार्य लगातार जारी है।

संवेदनशील और दुर्गम ग्रामों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित बीमारी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों की संयुक्त टीमों गांव-गांव पहुंचकर लोगों को स्वच्छ पेयजल, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दे रही हैं। जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाइयों, ओआरएस पैकेट, क्लोरिन टैबलेट, एंटीबायोटिक तथा अन्य चिकित्सा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने बताया कि मलेरिया, डेंगू और अन्य



मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करने, घरों के आसपास जलभराव नहीं होने देने तथा कूलर, पानी की टंकियों, गमलों और पुराने टायरों में जमा पानी को नियमित रूप से खाली करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने टायफाइड को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। डॉ. सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में दूषित पानी के कारण टायफाइड के मामलों में वृद्धि की आशंका रहती है। तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने और लगातार दो से पांच दिनों तक बुखार रहने पर ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। मौसम परिवर्तन के दौरान वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, गले में खराश और शरीर दर्द जैसी समस्याओं के बढ़ने की संभावना को देखते हुए नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भोजन से पहले हाथ धोने, उखला अथवा फिल्टर किया हुआ पानी पीने, बासी एवं दूषित खाद्य पदार्थों से बचने, खाद्य सामग्री को ढंककर रखने तथा ताजे और मौसमी फलों को आहार में शामिल करने की सलाह दी है।

जिला प्रशासन ने आमजन से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं और अपने परिवार को मौसमी एवं जलजनित बीमारियों से सुरक्षित रखने का आग्रह किया है।

जनपद सीईओ ने ली सचिव, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की बैठक

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

जनपद पंचायत महासमूह अंतर्गत गुरुवार को भोरिंग एवं पटेवा क्लस्टर में कुल 58 ग्राम पंचायतों के सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों एवं आवास मित्रों की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं पल्लेगशिप योजनाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह एवं जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने विशेष रूप से निर्देशित किया गया।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बी.एस. मंडवी द्वारा प्रथम पाली में भोरिंग



क्लस्टर अंतर्गत 28 ग्राम पंचायतों के सचिवों, आवास मित्रों एवं रोजगार सहायकों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इस दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समय-सिमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

सभी सार्वजनिक पेयजल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा जल जीवन मिशन के तहत संचालित पानी टंकियों में नियमित जल उपचार कराने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा नदी किनारे स्थित ग्रामों में संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने एवं विकास कार्यों में गति लाने निर्देशित किया।

हारी 35 नहीं सभी 90 सीटों पर भाजपा की हालत पतली है - कांग्रेस

रायपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में हालत खराब है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि समाचार आया है कि भाजपा हारी हुई सीटों पर फोकस करने जा रही है इसके लिए उसने निगम मंडल के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। भाजपा कुछ भी कर ले सारे भाजपा विधायकों के खिलाफ माहौल है तथा अबकी बार भाजपा के सारे मंत्री, विधायक चुनाव हारेंगे और बीजेपी छत्तीसगढ़ में सम्मानजनक विपक्षी दल के रूप में भी नहीं बचेगी। भारतीय जनता

पार्टी मुगलत में है अब उसे सारी सीटों में फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी मुश्किल से एक दर्जन सीटें भी नहीं जीतने की स्थिति में है। 2018



पार्टी मुगलत में है अब उसे सारी सीटों में फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी मुश्किल से एक दर्जन सीटें भी नहीं जीतने की स्थिति में है। 2018

विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड फिर से दोहराया जाएगा। प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछले द्वादश साल में भाजपा जनता का भरोसा खो

चुकी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि निगम मंडल आयोगों के पदाधिकारियों को शासन के द्वारा जो भत्ता, वाहन, स्टाफ की सुविधा

हुआ है। भाजपा निगम मंडल के पदाधिकारियों को मिली सुविधा अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए कर रही है, यह आपसिजनक है। सरकारी सुविधा का दुरुपयोग भाजपा के सांगठनिक काम के लिए किया जायेगा प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता से मोदी की गारंटी के नाम पर जो वादे किया था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। युवा, किसान, महिला, व्यापारी सभी भाजपा की सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी सरकार के सुशासन विहार में भी देखने को मिली।

सहूलियत, सम्मान और सेहत... हर घर नल से बदली जिंदगी

जगदलपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

रोज सुबह उठते ही घर में नल से साफ पानी आते देखने की खुशी क्या होती है, इसे कमली से पूछिए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव को अपने आंगन में लगे नल से आ रहे पानी की धार को दिखाते खुशी से उनकी आंखें डबडबा गईं। जल जीवन मिशन ने कमली जैसी हजारों महिलाओं को अमूल्य खुशियां दी हैं। कभी पीने और निस्तारी के पानी के लिए दिनभर थकित रहने वाली इन महिलाओं का जीवन घर में लगे नल ने बदल दिया है।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव अपने चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान जल जीवन मिशन का काम देखने कमली के भी गांव पहुंचे। कमली के गांव बस्तर जिले के तोकपाल



विकासखण्ड के दुगनपाल में उन्होंने कुछ और घरों में भी जाकर नल से पानी आते देखा। जल जीवन मिशन से घर में पानी पहुंचने की खुशी सभी महिलाओं के चेहरे पर दिख रही थी। जल जीवन मिशन दूरस्थ गांवों और वनांचलों की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। आधी आबादी के एक बड़े हिस्से को पीने के पानी के लिए रोज जूझना पड़ता था। खासतौर से

गर्मियों के दिनों में जब हर साल सिर पर पानी के बर्तन का सफर कुछ सौ मीटरों से कुछ किलोमीटरों में बदल जाता था। जीवन के लिए अनिवार्य जरूरत पानी की व्यवस्था गर्मियों में महिलाओं का जीवन दुष्कर बना देती थी। दुगनपाल में भी महिलाओं को रोज गांव के हंडंप या कुआं पर जाकर घर के सभी लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता था। घर में नल लग जाने से अब इस

समस्या से निजात मिल गई है। जल जीवन मिशन के काम जैसे-जैसे पूरे होते जा रहे हैं, महिलाओं की बाहर से पानी लाने की चिंता और तकलीफ दूर होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक साढ़े आठ हजार से अधिक योजनाओं को पूर्ण कर संचालन के लिए पंचायतों को सौंपा जा चुका है।

जल जीवन मिशन महज हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना नहीं है। यह महिलाओं की दिनचर्या और जीवन में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। गांवों में परंपरागत रूप से घर में पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी के इंतजाम का जिम्मा महिलाओं पर ही है। घर तक पानी की पहुंच न होने के कारण उन्हें हैंडंपो, सार्वजनिक नलों, कुंओं या अन्य स्रोतों से रोज पूरे परिवार के लिए जल संग्रहण

करना पड़ता है।

रोजाना का यह श्रमसाध्य और समयसाध्य काम बारिश तथा भीषण गर्मी के दिनों में और कठिन हो जाता है। कई इलाकों में गर्मियों में जल स्रोतों के सूख जाने के कारण दूर-दूर से पानी लाने की मजबूरी रहती है। परिवार के लिए पानी की व्यवस्था हर दिन का संघर्ष बन जाता है। महिलाओं के दिन के कई घंटे इसी काम में निकल जाते हैं।

जल जीवन मिशन हर घर तक नल से जल पहुंचाने के साथ ही महिलाओं को कई समस्याओं से निजात दिला रहा है। घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने से वे कई चिंताओं से मुक्त हो गई हैं। अब रोज-रोज पानी के लिए बहुत सारा श्रम और समय नहीं लगाना पड़ता।

कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा

जगदलपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा बस्तर संभाग के परीक्षार्थियों के लिए गुरुवार 11 जून 2026 को प्री-बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन अत्यंत कड़े सुरक्षा प्रबंधों और सख्त नियमों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। स्थानीय स्तर पर की गई व्यापक तैयारियों के साथ परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसके लिए जगदलपुर में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार प्री-बीएड की परीक्षा के लिए 9 केंद्र तय किए गए थे, जिनमें शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज धरमपुरा, बाल विहार हायर सेकण्डरी स्कूल, शासकीय दन्तेश्वरी पीजी महिला महाविद्यालय, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर



स्कूल पथरागुड़ा और शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल आसना को केंद्र बनाया गया था। नर्सिंग परीक्षा के लिए कुल 1,040 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 725 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 315 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार दोनों परीक्षाओं को मिलाकर बस्तर जिले में कुल 2,944 परीक्षार्थी शामिल हुए। स्क्रीन आलांनद स्कूल धरमपुरा, अग्रसेन चैक व रेलवे कालोनी शामिल रहे। इन 9 केंद्रों पर पंजीकृत कुल 2,938 परीक्षार्थियों में से 2,219 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 719 अनुपस्थित पाए गए। वहीं दूसरी ओर बीएससी नर्सिंग की परीक्षा शेष 4 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिनमें शहीद गुण्डाधूर कृषि कॉलेज कुम्हरावण्ड, धरम माहारा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक धरमपुरा, शासकीय हायर सेकण्डरी

खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड ने युवाओं से स्वरोजगार स्थापना हेतु मांगे आवेदन

जगदलपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुटीर व लघु उद्योग स्थापना कार्यक्रमों के तहत इच्छुक युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन और पारंपरिक कौशलों का संरक्षण भी किया जा सकेगा। ग्रामोद्योग विभाग के उप संचालक से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर शासन की ओर से अधिकतम 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है। इस योजना के अंतर्गत होटल, ग्राहक सेवा केंद्र, साइट सिस्टम, सिलाई, मोटर साइकिल व मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोकॉपी और स्टूडियो जैसी सेवा इकाइयों के साथ-साथ बेकरी, मिनी राइस मिल, वेलिंग वर्कशॉप, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, दोना-पतल, मसाला व मोमबत्ती निर्माण और बुटीक जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सेवा क्षेत्र में एक लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र में तीन लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है, जबकि हितग्राही को केवल पाँच प्रतिशत राशि स्वयं वहन करनी होती है, जो ग्रामीण युवाओं को छोटे-मोटे उद्योग शुरू करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाती है। योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक की प्रति, पैन कार्ड तथा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

बस्तर में लकड़ी माफिया बेलगाम, सीपीआई ने की न्यायिक जांच की मांग

कोंडागांव, (प्रतिदिन राजधानी)

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बस्तर संभाग में साल, आम, सेमल जैसी बेशकीमती कीमती लकड़ियों की अवैध कटाई पर रोक लगाने राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने इसे लेकर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में न्यायिक जांच समिति गठित करने की मांग की है।

संभागीय संयोजक बस्तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तिलक पांडे का आरोप है, कि बस्तर का जंगल उजड़ रहा और प्रशासन खामोश है। कोंडागांव सहित पूरे संभाग में लकड़ी माफिया खुलेआम फलदार और इमारती पेड़ों को काट रहे हैं। कटी लकड़ी की तस्करी दिनदहाड़े हो रही है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि यह सब शासन-प्रशासन की मिलीभगत या मौन सहमति के बिना संभव नहीं। जंगल कटने से बस्तर का पर्यावरणीय संतुलन चरमरा गया है। जैव-विविधता खत्म हो रही है, जल संकट गहरा रहा है। सबसे बड़ी मार आदिवासी समुदायों की आजीविका पर पड़ रही है।

कोंडागांव की ताजा घटना का उन्होंने ज्ञापन में जिक्र है। कुछ पत्रकारों ने लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़ किया। खबर में एक भाजपा नेत्री का नाम सामने आते ही खेल पलट गया। माफिया पर कार्रवाई के बजाय प्रशासन ने खबर छापने वाले मीडिया कर्मियों को ही निशाने पर ले लिया।



पत्रकार को सीधे कलेक्टर कार्यालय से उठाकर उस पर केस दर्ज कर दिया गया। सीपीआई ने कहा कि यह साबित करता है कि तस्करी के तार प्रशासन, वन विभाग और सत्ता के गलियारों से जुड़े हैं। सीपीआई की मांग है रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच समिति बने, जो 3 माह में रिपोर्ट दे। जांच तक सभी संदिग्ध अफसरों, नेताओं और माफिया पर एफ आई आर कर उन्हें निलंबित किया

जाए। जल्द लकड़ी का हिसाब हो और तस्करी के रास्ते सील किए जाएं। उजड़े जंगलों में तत्काल वन रोपण शुरू हो। पत्रकारों पर बदले की कार्रवाई वापस हो और उन्हें सुरक्षा मिले। दोषी चाहे किसी भी पद पर हो, सख्त सजा मिले। इस दौरान तिलक पांडे संभागीय संयोजक बस्तर, शैलेश जिला सचिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दिनेश कुमार, रामचंद्र मरकाम, सोमारु गावड़े आदि मौजूद रहे।

बस्तर के जंगलों में अब सुरक्षित होंगे वन्यजीव



जगदलपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

बस्तर के घने जंगलों और सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में वन्यजीवों की सुरक्षा तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए बस्तर वनमंडल ने एक संवेदनशील और अनूठी पहल की है। जंगलों के आसपास स्थित खुले और असुरक्षित कुओं पर लोहे की नेट लगाई जाएगी, जिसके तहत वन विभाग ने इन कुओं के चारों ओर पैरापेट वॉल यानी मुंडेर बनाकर उन्हें लोहे की मजबूत सुरक्षा जालियों से ढंकने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। यह पूरा अभियान मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वन वृत्त श्री आलोक तिवारी के कुशल मार्गदर्शन और बस्तर वनमंडलाधिकारी श्री उत्तम कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मानसून से पहले पूरा करने के लक्ष्य के साथ चलाया जा रहा है। वनांचलों और कृषि भूमि पर बने बिना मुंडेर के खुले कुएँ लंबे समय से मूक वन्य प्राणियों के लिए एक गंभीर और प्राणघातक खतरा बने हुए थे, जहां पानी की तलाश में या रात के अंधेरे में भटकते हुए तेंदुए, मात्तू और हिरण जैसे अनेक वन्यजीव अक्सर गिरकर असमय काल के गाल में समा जाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं से न केवल जैव-विविधता को अपूरणीय क्षति पहुँचती है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों में भी भय और असुरक्षा का माहौल बन जाता है।

आगामी मानसून सत्र में जलभराव की स्थिति को देखते हुए इस अभियान को तीव्र गति दी गई है, जिसके तहत वन विभाग के मैदान अमले ने संवेदनशील इलाकों का व्यापक सर्वे कर 29 ऐसे खतरनाक कुओं को चिह्नित किया है जिन्हें तुरंत सुरक्षित किया जा रहा है। उप-वनमंडलाधिकारियों और परिक्षेत्र अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में कुओं के चारों ओर मजबूत दीवार उठाकर उन्हें लोहे की भारी ग्रिल से ढंका जा रहा है, ताकि कोई भी जानवर दुर्घटना का शिकार न हो सके। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ वन्यजीवों के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय ग्रामीणों, खेलते हुए बच्चों और चरने वाले मवेशियों को भी हमेशा के लिए दुर्घटना के डर से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार यह ढांचागत सुरक्षा उपाय समाज के सभी वर्गों को एकसाथ संरक्षण प्रदान करते हुए एक समय जन-कल्याणकारी अभियान का रूप ले चुका है।

इस महत्वपूर्ण पहल को लेकर वनमंडलाधिकारी श्री उत्तम कुमार गुप्ता ने कहा कि वन्यजीव हमारी प्राकृतिक पारिस्थितिकी के अभिन्न अंग हैं और उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बस्तर वनमंडल में 29 संवेदनशील कुओं को चिह्नित कर उन्हें सुरक्षित बनाया जा रहा है और इस अभियान की पूर्ण सफलता के लिए वन विभाग स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वन प्रबंधन समितियों तथा आम नागरिकों से भी सक्रिय सहयोग की अपील करता है, ताकि बस्तर के वन्य प्राणियों को एक सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही वन विभाग ने जागरूक नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा खुला या असुरक्षित कुआं स्थित हो, तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी वन परिक्षेत्र कार्यालय को दें और वन्यजीव संरक्षण को अपना सामूहिक सामाजिक दायित्व समझकर बस्तर की अमूल्य जैव-विविधता को बचाने में अपनी भागीदारी निभाएं।

दुर्ग, (प्रतिदिन राजधानी)

अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन संस्थानों, आवासीय परिसरों, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, छात्रावास, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य बड़े परिसरों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, उन्हें अपने परिसर में उत्पन्न गीले (जैविक) कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण एवं निपटान स्वयं परिसर के भीतर ही करना होगा।

इसके लिए कम्पोस्टिंग, बायोगैस, बायो-मीथेनेशन अथवा अन्य स्वीकृत तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लागू किए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी थोक अपशिष्ट उत्पादकों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त सुमित

मोर गांव- मोर पानी- मोर तरिया



विजय मिश्रा 'अमित' अग्रोहा
कॉलोनी रायपुर 492013

छत्तीसगढ़ शासन का एक महाअभियान 'मोर गांव- मोर पानी- मोर तरिया' की शुरुआत जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसे साकार करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में दस हजार आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एक नया अभियान 'नवा तरिया आय के जरिया' के तहत पांच सौ नए तालाबों के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं को भूजल स्तर में गिरावट को रोकने, जल संग्रहण, सिंचाई सुविधा का विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से बहुउद्देशीय योजना कहना उचित होगा।

ऐसी योजनाएं जनमानस में नई उम्मीदें का संचार करती हैं। जीते जी नए सपनों को देखते हुए निर्धन ग्रामीण आमजन सुखद

भविष्य कि आस लगाते हैं। इन्हें पूरा करके सरकार जहां खास पहचान बनती है वहीं कागज पर ही दर्ज होकर रह जाए तो जनमन की आस फंस बनकर रह जाती है और सरकार के लिए गले की हड्डी भी बन जाती है।

सरकार की ऐसी योजना को लेकर टीवी पर आ रही खबर को सुनकर मेरे बच्चे ने पूछा- पापा जी तालाब क्या है ? तालाब के प्रति बच्चों का अनजानापन मुझे अपराधबोध करा गया। नवपीढ़ी को अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज और संस्कारों से अनजान बनाने का काम हम स्वयं कर रहे हैं। अपनी इस भूल को सुधारने मैंने बच्चों को अनेक तालाब दिखाए, ताकि वे "तालाब की आब" को समझ सकें।

तालाबों को देखकर बच्चों ने नाक-भौं सिकुड़ते हुए कहा- छी...छी ... इतनी गंदी जगह, इतने गंदे पानी में आप नहाते थे ? आपको "स्कीन डिजीज" नहीं होती थी ? बच्चों की बातों से मैं आहत हुआ। मुझे लगा तालाब भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा होगा। बच्चों को कौन समझाए कि तालाब आज क्या से क्या हो गये हैं। लगभग साठ दशक पूर्व की बात है जब रायगढ़ जिले के करीब स्थित गाँव "जतरा" में प्राइमरी स्कूल में अध्ययनरत रहते हुये अपने सहपाठियों के साथ तालाब का पानी पीकर हम प्यास बुझाया करते थे। तालाब के अंदर घुटने की गड़गड़ाहट तक हम घुस जाते थे और झुककर सीधे तालाब के ऊपरी जल स्तर पर मुंह सटाकर बेझिझक पानी पी लिया करते थे। प्यास बुझाने का यह क्षण हमारे लिये बड़ा मजेदार और तृप्तिदायक हुआ करता था, किन्तु अब नई पीढ़ी हमारी इस हरकत को "आदिमानव" की प्रवृत्ति करार देगी। सच ही तो है बंद बोतल का पानी पीने वाली नई पीढ़ी स्वच्छ जलाशय में एकत्रित प्रकृति प्रदत्त जल के स्वाद को भला कैसे समझ पायेगी। जनसामान्य को जल आपूर्ति करने सहित

वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत साधन और "ग्राउन्ड वॉटर लेबल रीचार्ज" के भी तालाब उत्कृष्ट पात्र थे। जीव जन्तुओं की प्यास बुझाने वाले ये जलागार "वसुधैव कुटुम्बकम्" की अवधारणा को प्रबल बनाते थे। तालाबों के तट पर आम,बरगद, पीपल, नीम के हरे-भरे वृक्षों पर तोता-मैना, बुलबुल, पंखला जैसे पक्षियों का कर्ण प्राय कलरव से मन गदगद हो जाया करता था। तालाब के पार पर देवालयों की स्थापना होती थी, जहाँ पर्व विशेष पर बड़े बड़े मेला लगते थे।

गाँव से लेकर शहरों में तालाबों की उपादेयता के कारण ही तालाबों को देवस्थान की तरह पूज्य माना जाता था। अब तो स्थिति ठीक इसके विपरीत हो चुकी है। स्वच्छ सुंदर तालाब देखना अब ख्वाब सा हो गया है। तालाबों में जलकुंभी का साम्राज्य हो गया है। तालाब अब जानवरों के नहाने का स्थान बनकर रह गये हैं। यह एक बड़ी विडम्बना है कि तालाबों की हिफाजत एवं संरक्षण के प्रति आलस चहुँ ओर हद-दर्ज तक लापरवाही दिखाई दे रही है। इनकी स्वच्छता संरक्षण का सीधा दायित्व आमजन के कंधे पर ही है, किन्तु विकास की सीढ़ी चढ़ते लोग अपने पुरखों की पीढ़ी को किस तरह से बर्बाद करते हैं उसका जीवन्त उदाहरण गाँव-शहर में कचरे, पॉलिथीन से पट्टे, गंदगियों से बजबजाते तालाब हैं।

इतिहास के पन्नों में दर्ज अनेक तालाब अब "जमीन के लालची" लोगों के हाथ दफन होकर अपनी पहचान खो चुके हैं। शहरों के बाद अब गाँव गाँव में नल, नलकुंभों से पानी मिलने लगा है तो तालाब से लोगों ने न केवल मुंह फेर लिया है, बल्कि इसे कचरा-कूड़ा, मल-मूत्र फेंकने की जगह बना लिया है। शहर भर की नालियों का अंत तालाबों में ही होता दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार के केमिकल पदार्थों से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियों विसर्जन से भी तालाब के पानी प्रदूषित हो

रहे हैं। एक जमाना था जब लोग स्वच्छ से श्रमदान करके तालाबों का गहरीकरण और सफाई अभियान में जुटते थे। आज वही लोग इन कार्यों के लिये शासन की ओर मुंह ताकते दिखाई दे रहे हैं। यह भी देखने में आया है कि सरकारी बजट पर तालाबों के सौंदर्यकरण का प्रयास भी किया गया तो लोगों ने वहाँ की रेलिंग और सीमेंट निर्मित घाट को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा।

धर्माचरण करने में आज भी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत आगे है। यहां पर तो जनम-मरण में तालाब का कार्यक्रम विशेष रूप से रखा जाता है। अगर इन्हीं धर्मावलम्बियों में एकजुटता आ जाये, तालाबों के संवर्धन-संरक्षण की जिद घर घर जाये तो एक बड़े चमत्कारिक परिणाम की आशा की जा सकती है। बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएँ प्रदेश में, नगर में सक्रिय हैं। तालाबों के प्रति उदासीन हो चुके लोगों को जगाने की महती जिम्मेदारी इन पर है। अगर अपनी प्राथमिकताओं में तालाब संरक्षण को ये शामिल कर लें तो निश्चित रूप से गाँव शहर के बढ़ते तापमान, घटते जलस्तर को रोकने का आत्मसंतोष इन्हें अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही नई पीढ़ियों में भी जलागारों के प्रति आदर भाव जगाने की दिशा में कारगर प्रयास होगा।

विकास के लिये मची अंधी दौड़ की होड़ में तालाबों के अस्तित्व पर गहराते संकट भविष्य में लाईलाज नासूर बनने का संकेत अब स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। इसका आंकलन करके छत्तीसगढ़ सरकार ने तालाबों के गहरीकरण, जलसंग्रहण का कार्य जनसहयोग से गंभीरतापूर्वक आरम्भ किया गया है। यह अत्यन्त हर्ष की बात है। ऐसे बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय के कार्यों से जुड़े पवित्र हाथों के साथ जुड़ने का संकल्प लेते हुये कहना उचित होगा- आईये तालाब को साफ करें, तालाब संरक्षकों को आदाब करें।

एमेजॉन भारत का सबसे भरोसेमंद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभरा

बिलासपुर। भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल कॉमर्स के ईकोसिस्टम को काफी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है ग्रामक इंटरफेस डिजाइन, जिन्हें "डार्क पैटर्न" के रूप में जाना जाता है। डेटम इंटीलिजेंस की "डार्क पैटर्नस इन इंडियाज ऑनलाइन मार्केटप्लेस" रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय ग्राहकों को डार्क पैटर्न की वजह से हर साल 25,000 करोड़ रुपये से 28,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो रहा है। देश के 304 मिलियन ऑनलाइन खरीदारों में से 88 प्रतिशत को प्रतिमाह औसतन 78 रुपये से 87 रुपये का नुकसान होता है। यह सर्वे साल 2026 की पहली तिमाही में 50 शहरों के 2,590 से अधिक ग्राहकों के बीच किया गया। इसमें क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रेवल में 12 मुख्य प्लेटफॉर्म के बारे में सवाल पूछे गए थे। सर्वे में डार्क पैटर्न, ग्राहकों पर उनके वित्तीय प्रभाव और विश्वास उनके असर का आकलन किया गया। सर्वे में सामने आया कि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्लेटफॉर्म के बीच 92 पॉइंट का अंतर है।

Amazon.in पर दोपहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 2 गुना वृद्धि, टियर 2 और टियर 3 शहर ऑनलाइन खरीदारी को दे रहे हैं बढ़ावा...

बेंगलुरु। अमेजन ने घोषणा की है कि Amazon.in पर उसके दोपहिया वाहन स्टोर ने साल-दर-साल 2 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इसकी मांग का नेतृत्व टियर 2 और टियर 3 शहर कर रहे हैं, जहां ग्राहक रोजमर्रा की कम्प्यूटर बाइक्स के साथ-साथ प्रीमियम और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी तेजी से चुन रहे हैं। कंपनी वर्तमान में इलेक्ट्रिक, प्रीमियम और कम्प्यूटर सेगमेंट में 20 से अधिक ब्रांडों के विकल्पों को लिस्ट करती है, जिनमें ट्राम्प, केटीएम, रॉयल एनफील्ड, बजाज ऑटो, एथर एनजी और हीरो मोटोकॉर्प शामिल हैं, जिन्हें 3,000 से अधिक ऑईएम अधिकृत डीलरों का समर्थन प्राप्त है। अमेजन इंडिया के निदेशक - होम, किचन एंड आउटडोर, अमन लोहान ने कहा, 'भारत में दोपहिया



वाहन खरीदने का सफर अक्सर लंबा होता है और भ्रमित करने वाले विकल्पों, ईंधन के प्रकारों और कीमतों के कारण यह तनावपूर्ण हो सकता है। यह तब और अधिक सीमित महसूस होता है जब आपके पास सीमित विकल्प हों, खासकर महानगरों से बाहर। ग्राहकों के लिए, Amazon.in एक ही स्थान पर ब्रांडों, मूल्यों बिंदुओं और ईंधन प्रकारों के सबसे बड़े

विकल्प लेकर आता है, जिसमें पूरी कीमत पारदर्शिता और डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलती है। ब्रांडों के लिए, यह उनकी पहुंच का विस्तार करता है। पिछले दो वर्षों में, हमने दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सही विकल्प, साधन और पहुंच तैयार कर ली है और इस पूरे साल हम इसका और विस्तार करना जारी रखेंगे।

ग्राहक चुन रहे हैं प्रीमियम विकल्प

: ईंधन के सभी प्रकारों में, ग्राहक प्रीमियम फोर्स, कनेक्ट टेकनोलॉजी, उन्नत सुरक्षा प्रणाली और दीर्घकालिक ओनरशिप वैल्यू वाले मॉडल चुन रहे हैं। Amazon.in पर खरीदे गए दोपहिया वाहन की औसत कीमत अब 1 लाख से अधिक है, जो उच्च-विशिष्ट मॉडलों की ओर एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है।

प्रीमियम मोटरसाइकिलों में साल-दर-साल लगभग 5 गुना वृद्धि हुई, जबकि कम्प्यूटर बाइक्स दोगुने से अधिक हो गईं और आईसीई स्कूटरों में इसी अवधि के दौरान 1.5 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए, 1 लाख से 1.5 लाख का सेगमेंट अब Amazon.in पर कुल ईवी मांग का आधे से अधिक हिस्सा है, जो शुरूआती स्तर के विकल्पों से मिड-प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव को दिखाता है। Amazon.in पर दोपहिया वाहनों की मांग मुख्य रूप से महानगरों से बाहर से आ रही है। लगभग हर तीन में से दो ग्राहक टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं, जबकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के मामले में यह हिस्सेदारी बढ़कर हर दस में से सात

ग्राहकों तक पहुंच गई है। इन शहरों में वृद्धि की गति लगातार तेज हो रही है। दक्षिण भारत के काकोनाडा, तिरुपति और नेल्लोर में बुकिंग्स में वर्ष-दर-वर्ष 12 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर भारत के नागौर और जौड़ तथा पश्चिम भारत के जामनगर, बिलासपुर और राजकोट में दोपहिया वाहन बुकिंग्स में वर्ष-दर-वर्ष 6 गुना तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं, पूर्व भारत के पूर्णिया और समस्तीपुर में बुकिंग्स में 7 गुना तक की वृद्धि हुई है, जो नए मांग केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। यह उपभोक्ता व्यवहार में आ रहे एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां ग्राहक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए तेजी से ऑनलाइन माध्यम को अपना रहे हैं।

बॉलीवुड समाचार

काम दिलाने की आड़ में दोगे गए 20 लाख रुपए... मेरा मजाक उड़ाया गया, 'दिलबर' जैसे कई गाने फ्री में करने पड़े : नोरा फतेही



मुंबई की चमक-दमक के पीछे ठगी, ताने और संघर्ष की लंबी कहानी भी छुपी है। नोरा फतेही की जिंदगी भी ऐसी ही रही, जहां काम दिलाने का वादा कर 20 लाख रुपए टग लिए गए और कई बार उन्हें बिना फीस के गाने करने पड़े। 'मेरा मजाक उड़ाया गया, दिलबर जैसे कई गाने फ्री में करने पड़े' - यह दौर उनकी पहचान बनने से पहले के संघर्ष को दिखाता है। कनाडा से मुंबई आई नोरा ने वेंटर से लेकर ऑडिशन तक हर रास्ता अपनाया, लेकिन हार नहीं मानी। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी स्टारडम की सबसे बड़ी ताकत बना।

छिपकर डांस करती थीं नोरा, नहीं ली ट्रेनिंग; मां ने डांट और पिटाई भी की

नोरा का जन्म एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ। घर में डांस को लेकर कड़ा विरोध था, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही डांस का जुनून था। उन्होंने कभी प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग नहीं ली। वे अलग-अलग डांस स्टूडियो देखकर और लगातार प्रैक्टिस से सीखती रहीं। नोरा बचपन में घर के अंदर बंद कमरे में छिपकर डांस करती थीं। उन्हें डर रहता था कि परिवार को पता चल गया तो डांट पड़ेगी। एक बार उनकी मां ने उन्हें डांस करते देख लिया, जिसके बाद उन्हें डांट और सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यहां तक की मां ने पिटाई भी की। विरोध के बावजूद नोरा ने डांस करना नहीं छोड़ा और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करती रहीं। परिवार के विरोध और मुश्किल माहौल के बीच उन्होंने पढ़ाई पूरी की और इसके बाद भारत आने का फैसला किया। उनका सपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम बनाने और खुद को डांसर व परफॉर्मर के रूप में स्थापित करने का था।

5,000 रुपए लेकर मुंबई आई थीं

नोरा फतेही 2014 में बॉलीवुड में करियर शुरू करने के लिए केवल 5,000 लेकर मुंबई पहुंची थीं। नोरा कहती हैं- मुझे यह भी नहीं पता था कि 1000 डॉलर क्या होते हैं। मैं एक अपार्टमेंट में नौ लड़कियों के साथ रहती थी। वहां अक्सर सोचती थी कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ।

'बिग बॉस 9' से मिली पहचान

साल 2015 में नोरा को टीवी के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 9' में हिस्सा लेने का मौका मिला। शो में उनका सफर लंबा नहीं रहा, लेकिन इससे उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने कई डांस परफॉर्मस और फिल्मों में छोटे-बड़े मौके हासिल किए। नोरा फतेही ने 2014 में फिल्म 'रोर: टागर्स ऑफ द सुंदरबन्स' से बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद उन्हें साउथ इंडस्ट्री से भी कई फिल्मों के ऑफर मिले। नोरा 2015 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'बाहुबली' के गाने 'मनोहरी' में नजर आई थीं।

एक के बाद एक दिए सुपरहिट डांस नंबर

'दिलबर' की सफलता के बाद नोरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 'कमरिया', 'ओ साकी साकी' और 'गर्मी' जैसे कई सुपरहिट गानों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। देखते ही देखते वह बॉलीवुड की लोकप्रिय डांस परफॉर्मर्स में शामिल हो गईं।

हिंदी न आने पर उड़ाया जाता था मजाक

नोरा ने बताया कि भारत आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती भाषा थी। हिंदी न जानने की वजह से ऑडिशन में उन्हें बार-बार रिजेक्ट किया जाता था। कई बार लोग उनके उच्चारण और एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाते थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहीं।

'दिलबर' ने बदल दी जिंदगी

नोरा के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2018 में आया, जब फिल्म 'सत्यमेव जयते' का गाना 'दिलबर' रिलीज हुआ। यह गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ और नोरा रातोंरात देशभर में चर्चा में आ गईं। उनके डांस स्टाइल, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्सप्रेशन ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

बिना पैसे के काम करने पड़े

हालांकि, करियर की शुरुआत में उन्हें फिल्मों में पैसे नहीं मिलते थे। नोरा कहती हैं- 'दिलबर' के अलावा भी मैंने कई गाने फ्री में किए हैं। उस समय पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं फिल्म इंडस्ट्री में खुद को प्रूव करना चाहती थी, इसलिए पैसे की डिमांड नहीं की। इंडस्ट्री में लोगों के पास बहुत ऑप्शन हैं। मैं नहीं तो कोई और करेगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात मौका मिलना था।

लगा था मुंबई पहुंचते ही स्टार बन जाएंगी

नोरा कहती हैं- फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मुझे लगा था कि मुंबई पहुंचते ही स्टार बन जाऊंगी। मैंने कपड़े पैक किए और मुंबई आ गई। यहां आने के बाद पता चला कि बहुत कुछ सीखना है। मुझे हिंदी नहीं आती थी। हिंदी मेरे लिए विदेशी भाषा थी। सबसे पहले हिंदी सीखी और खुद को परफॉर्मर के तौर पर तैयार किया।

केटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस से मिली प्रेरणा

नोरा कहती हैं- मैंने बॉलीवुड में कभी काम करने के बारे में नहीं सोचा था। इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने 'देवदास' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्में देखी थीं। मुझे लगा था कि रिफर् इंडियन लड़कियां ही बॉलीवुड में पकड़े बन सकती हैं। बॉलीवुड में काम करने की प्रेरणा मुझे केटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस से मिली। फिर मैंने बहुत ऑडिशन देने शुरू किए।

गुजराते के लिए किया वेंटर का काम, बेचे लॉटरी टिकट

स्टगल के दिनों में आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें गुजराते के लिए छोटे-मोटे काम करने पड़े। नोरा ने कॉफी शॉप में वेंटर का काम किया और लॉटरी टिकट भी बेचे। मॉडलिंग और छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, लेकिन कई बार काम के बाद भी भुगतान नहीं मिलता था।

कई दिन सिर्फ ब्रेड और अंडे खाकर बिताए

नोरा के लिए सबसे मुश्किल समय वह था जब पैशों की कमी के कारण उन्हें खाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि कई बार दिनभर सिर्फ ब्रेड और अंडे खाकर गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने मुंबई छोड़ने का विचार नहीं किया और अपने सपनों के लिए उड़ी रही।

गाने पर हुआ विवाद, मांगनी पड़ी थी माफी

नोरा फतेही हाल ही में फिल्म 'केडी : द डेविल' के गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर विवादों में घिर गई थीं। गाने के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसके बोल और प्रस्तुति पर आपत्ति जताई गई। कई लोगों ने आरोप लगाया कि गाने में महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है। मामला बढ़ने के बाद यह राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया। विवाद के बाद आयोग ने नोरा समेत गाने से जुड़े अन्य लोगों को पेश होने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान नोरा आयोग के सामने पहुंची और लिखित रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भयानाओं को दूर करना नहीं था और एक कलाकार के तौर पर वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझती हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, नोरा ने आयोग को बताया कि उन्होंने गाने की शूटिंग एक अलग क्रिप्टिव विजन के तहत की थी और रिलीज के समय हुए कुछ बदलावों की उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी।

सौरव गांगुली बिग बॉस बांग्ला सीजन 3 की करेंगे मेजबानी

पूरे 10 साल के इंतजार के बाद बांग्ला दर्शकों के लिए फिर से रियलिटी शो बिग बॉस लौटने का रवारा है। निर्माताओं ने बिग बॉस बांग्ला सीजन 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, जिसने दर्शकों में जबरदस्त उत्साह का संचार किया है। यह घोषणा न केवल इस शो के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर है, बल्कि यह बांग्ला टीलेविजन उद्योग में मनोरंजन के एक नए युग का भी संकेत देती है। शो का मंचन एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और इसके हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है ताकि दर्शकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान किया जा सके। इस सीजन की सबसे बड़ी और आकर्षक खासियत यह है कि शो को बांग्ला के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली होस्ट करते नजर आएंगे। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए एक विशेष वीडियो में सौरव गांगुली की झलक दिखाई गई है, जिसने फैंस को उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली का टेलीविजन पर आना हमेशा से दर्शकों के लिए रोमांचक



रहा है, और उनकी होस्टिंग दर्शकों को शो से बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। घोषणा करते हुए मेकर्स ने लिखा, भारत के सबसे बड़े मनोरंजन का मंच अब बांग्ला में आ रहा है। मनोरंजन का बॉस - बिग बॉस बांग्ला जल्द आ रहा है। यह टेलीविजन अपने आप में शो की भव्यता और मनोरंजन के स्तर को दर्शाती है। बिग बॉस बांग्ला सीजन 3 को एंडेमोल शान, इंडिया लेकर आ रहा है, जो बिग बॉस एंटरटेनमेंट का एक अभिन हिस्सा है। यह

कंपनी लंबे समय से भारतीय दर्शकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल फॉर्मेट्स को स्थानीय रूप में पेश करती रही है और कई सुपरहिट शोज बना चुकी है। एंडेमोल शान इंडिया और बिग बॉस एशिया ने पिछले कुछ वर्षों में कई चर्चित वेब सीरीज और शो दर्शकों को दिए हैं। इनमें द नाइट मैनेजर, द ट्रायल, होस्टेज और कॉल माय एजेंट: बॉलीवुड जैसी सीरीज शामिल हैं, जिन्होंने अपनी गुणवत्ता और सामग्री से दर्शकों को प्रभावित किया है। वहीं, नॉन-

स्क्रिप्टेड कंटेंट में द कपिल शर्मा शो, एमटीवी रोडीज, इनूट द वाइल्ड विद बेयर गिरलस और टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया जैसे लोकप्रिय शो भी कंपनी के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, जो इनकी बहुमुखी प्रतिभा और मनोरंजन जगत में मजबूत पकड़ को दर्शाते हैं। बिग बॉस भारत के सबसे सफल रियलिटी प्रेंचार्जो ब्रांड्स में गिना जाता है। यह शो देशभर में 7 अलग-अलग भाषाओं में 69 से अधिक सीजन पूरे कर चुका है, जो इसकी अपार लोकप्रियता और सांस्कृतिक पहुंच का प्रमाण है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और अन्य भाषाओं में इसकी लोकप्रियता पहले ही साबित हो चुकी है। अब बांग्ला दर्शकों को भी एक बार फिर यह मनोरंजन का बड़ा मंच मिलने जा रहा है, जिससे उन्हें अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज को एक अलग अंदाज में देखने का मौका मिलेगा। बिग बॉस बांग्ला की वापसी और सौरव गांगुली की होस्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शो के प्रतियोगियों, प्रीमियर डेट और अन्य जानकारीयों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म 'काला हिरण' का फर्स्ट लुक रिलीज... नाम बदलकर सलमान खान और लॉरेंस का जिक्र किया गया

सलमान खान के चर्चित काला हिरण मामले से प्रेरित फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। फिल्म का पहला वीडियो शूकवार को रिलीज हुआ। जिसमें सलमान खान का जिक्र अयान खान और लॉरेंस का जिक्र लॉयन के नाम से किया गया है। वीडियो में काला हिरण शिकार केस और कानूनी लड़ाई से जुड़े मामले को दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन भारत एस. श्रीनाथ ने किया है। जबकि अमित जानी इसके लेखक और निर्माता हैं। फिल्म का टीजर 20 जून को रिलीज किया जाएगा।

'काला हिरण' को लेकर सलमान ने लीगल नोटिस भेजा : 'काला हिरण' को लेकर सलमान की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया था। सलमान की ओर से लॉ फर्म डीएसके लीगल ने कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे को एक लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में 'काला हिरण' नाम की प्रस्तावित फिल्म के प्रोडक्शन और प्रमोशन को तुरंत रोकने की मांग की गई।

सलमान की ओर से मिले लीगल नोटिस को फाड़ : फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सलमान खान की ओर से मिले लीगल नोटिस को फाड़ दिया था। हर कोई मुझसे पूछ रहा है, मीडिया, दोस्त, कि सलमान खान के नोटिस पर आपको क्या कहना है?



इस नोटिस पर मैं क्या कहूँ? पिछले 36 घंटों से उनकी डोंगरी, धारावी, जोगेश्वरी के मुस्लिम लड़कों की फैन फॉलोइंग, उनके टूलकित ने मुझे जान से मारने में चले जाइए, आपकों कैसे लो ग मिल जाएंगे जो अपनी सूझबूझ से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेते हैं। इसको वजह सिर्फ कितानों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव होते हैं। भारत में हम 'जुगाड़' को अपनी खास ताकत मानते हैं और यही बात भारतीयों को हर क्षेत्र में अलग पहचान दिलाती है। जह मैंने 'इंडिया के टॉप 1%' का फॉर्मेट देखा, तो यह मुझे तुरंत पसंद आया। यह ऐसा शो नहीं है जो आपसे इतिहास की तारीखें पृष्ठ, बल्कि यह

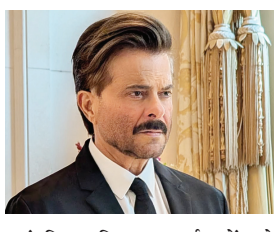
फिटनेस, अनुशासन और थोड़ी-सी मौज-मस्ती! सोनी सब के कलाकारों ने अपने पसंदीदा 'चीट मीलस' के बारे में बताया

मुंबई। स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना अनुशासन, सोच-समझकर खाने और निरंतरता का मांग करता है, लेकिन हर किसी का एक ऐसा चीट मील होता है, जो सारी मेहनत को सार्थक बना देता है। फिटनेस और संतुलित खानपान अहम हिस्सा है, लेकिन वे मानते हैं कि कभी-कभी की गई छोटी-सी इंडजेंस भी उतनी ही जरूरी है। आराम देने वाले क्लासिक्स से लेकर लजीज स्ट्रीट फूड और स्वादिष्ट डेजर्ट तक, ये कलाकार बताते हैं कि कौन-सी स्ट्रीट उन्हें सबसे ज्यादा खुशी

देती है। इब्रकाल खान, जो यादों में डॉ. देव का किरदार निभा रहे हैं, ने साझा किया, 'मैं आमतौर पर साफ-सुथरा खाने और फिटनेस रूटीन में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यदि कोई चीट मील है, जिसमें कभी मना नहीं कर सकता, तो वह बिरयानी है। एक अच्छी तरह से बनी बिरयानी खाने का मजा ही अलग होता है। मेरा मानना है कि फिटनेस का मतलब बैलेंस है और कभी-कभी अपने पसंदीदा खाने का मजा लेना बिल्कुल ठीक है।' गुलकी जोशी, जो यादों में डॉ. सुष्टि अग्रवाल का किरदार निभा रही हैं, ने कहा, 'मैं खाने को लेकर सजग रहने

की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे मीठा बहुत पसंद है। मेरा चीट मील अक्सर किसी रिच चॉकलेट डेजर्ट से जुड़ा होता है, चाहे वह केक हो, ब्राउनी हो या आइसक्रीम। मेरा मानना है कि फिटनेस कभी सजा जैसी नहीं लगनी चाहिए। यदि आप अपने रूटीन में लगातार बने रहते हैं, तो कभी-कभी खुद को ट्रीट देने के बिल्कुल हकदार हैं।' मुस्कान बामने, जो पुष्पा इम्पॉसिबल में शानाया का किरदार निभा रही हैं, ने साझा किया, 'मैं खाने को लेकर सजग रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पानीपुरी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे मैं अपने ड्राइव में कितनी भी अनुशासित रहूँ, पानीपुरी को कभी मना नहीं कर सकती।

मुंबई। स्टार प्लस अपने टेलीविजन दर्शकों के लिए एक नया और अलग अनुभव लेकर आ रहा है। जी हाँ, चैनल अपना नया रियलिटी शो 'इंडिया के टॉप 1%' पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे अनिल कपूर होस्ट करेंगे। यह शो प्रतिभागियों की समझ, तर्कशक्ति, नजरिए और तेजी से फैसले लेने की क्षमता को परखने वाला एक रोमांचक मुकाबला होगा। आज के दौर में, जहाँ हर तरफ जानकारी की भरमार है, 'इंडिया के टॉप 1%' एक अलग सवाल पृष्ठ है - क्या आप अपनी सोच और समझ के दम पर सबसे आगे निकल सकते हैं? यह शो



पारंपरिक विजय कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है, जहाँ सिर्फ याद की हुई जानकारी या कितानों का ज्ञान मायने नहीं रखता। इस नए फॉर्मेट में तर्कशक्ति, सामान्य समझ, तेज सोच और दबाव में सही फैसला लेने की क्षमता को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। शो में आने वाली हर चुनौती

इस बात की परीक्षा होगी कि प्रतिभाग्य जानकारी को कितनी जल्दी समझते हैं, पैटर्न को कैसे पहचानते हैं, चले जाइए, आपकों कैसे निकालते हैं और अहम समय पर कितनी तेजी से सही निर्णय लेते हैं। जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, चुनौतियाँ भी कठिन होती जाएँगी और सबसे तेज दिमाग वाले प्रतिभाग्य ही अंत तक टिक पाएँगे। सभी का लक्ष्य एक ही होगा भारत के टॉप 1% सोचने-समझने वाले लोगों में अपनी जगह बनाना। शो के बारे में बात करते हुए, अनिल कपूर ने कहा, 'मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत ऐसे लोगों का देश है, जिनकी

देखता है कि दबाव की स्थिति में आपका दिमाग तर्क और सामान्य समझ के आधार पर कितना बेहतर काम करता है। यही बात इसे सबसे अलग बनाती है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं स्टार प्लस पर इस शो को होस्ट करने को लेकर बेहद उत्साहित हूँ। यह मंच लोगों को अपनी सोचने-समझने की क्षमता दिखाने का मौका देगा, जो भारतीयों की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। इस सफर का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।' अनिल कपूर द्वारा होस्ट किया जाने वाला 'इंडिया के टॉप 1%' जल्द ही स्टार प्लस पर प्रसारित होगा।

गांव-शहर चलो अभियान-प्रशासन पहुंचा जनता के द्वार, समस्याओं का होगा समयबद्ध समाधान

मुंगेली, (प्रतिदिन राजधानी)

कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले में आमजनों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने अभिनव पहल की जा रही है। यह अभियान जिले में प्रशासन और जनता के बीच सतत संवाद एवं प्रभावी संपर्क का मजबूत माध्यम बनकर उभर रहा है। सुशासन तिहार के बाद शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर जमीनी स्तर पर समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं तथा पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।



कलेक्टर ने जिले में गांव-शहर चलो अभियान की पहल करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को आगामी 15 दिनों तक क्षेत्र भ्रमण कर जमीनी स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुशासन तिहार के बाद यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच सतत संवाद एवं प्रभावी संपर्क का मजबूत माध्यम बनेगा।

इससे छूटे हुए पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने प्रयास किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं, बल्कि मौके पर समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंचकर उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझ रहा है, जिससे शासन की योजनाओं

का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचा सकेगा। अभियान के अंतर्गत पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया अंतर्गत ग्राम सुरही, महासाई, डगनिया तथा उनके आश्रित पारा डोगरीपारा, ग्रामीणों एवं पशुपालकों को पशुओं में होने वाली मौसमी बीमारियों, टीकाकरण एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों को सभी पशुओं का समय पर टीकाकरण कराने की सलाह दी गई। अभियान

अंतर्गत कृषि विभाग के उपसंचालक ने खाद वितरण केंद्रों एवं निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि किसानों को सुगमता से खाद उपलब्ध कराने के लिए पानी, टेंट एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी प्रकार खाद्य अधिकारी एवं डीएम नॉन के द्वारा अचानकमार क्षेत्र के पहुंचविहीन ग्रामों छपरवा, महासाई में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया।

गोगो रैपर के साथ आरोपी गिरफ्तार पान ठेलों में चोरी-छिपे करता था बिक्री

रायगढ़, (प्रतिदिन राजधानी)

9 जून की रात्रि थाना साइबर सेल एवं थाना कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा रायगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नशे के रूप में उपयोग किए जाने वाले गोगो रैपर की बिक्री के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है।



संदेही सुरेन्द्र कुमार छाबड़ा (38) सिंधी कॉलोनी पक्की खोली चक्रधरनगर के कब्जे से दो कार्टूनों में 20 डिब्बों में कुल 1120 नग गोगो रैपर बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि उक्त गोगो रैपर के अंदर तंबाकू, युक्त फ्लेवर या गांजा

भरकर नशे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पूछताछ के दौरान संदेही ने बताया कि वह उक्त गोगो रैपर को तिल्दा, जिला रायपुर से लगभग 14,500 रुपये में खरीदकर रायगढ़ लाया था और शहर के विभिन्न पान ठेलों में चोरी-छिपे बेचता था। अनावेदक सुरेन्द्र कुमार छाबड़ा के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उसकी गतिविधियों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 170 123 एवं 135(क) के तहत भी कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

जिले की सेवा सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत बीज भंडारण

मुंगेली, (प्रतिदिन राजधानी)

खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों के तहत जिले में किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उप संचालक कृषि श्रीमती वीणा ठाकुर ने बताया कि खरीफ फसल के लिए 17 हजार 955 क्विंटल बीज की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध बीज निगम द्वारा 19 हजार 734 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है। इससे जिले में बीज की उपलब्धता मांग से भी अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी 66 सेवा सहकारी समितियों में 15 हजार 630 क्विंटल बीज का

भंडारण किया जा चुका है, जो निर्धारित मांग के अनुरूप शत-प्रतिशत से अधिक है। उपलब्ध बीजों में धान, अरहर, मूंग, मूंगफली एवं ढेंचा जैसी प्रमुख फसलों के बीज शामिल हैं। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा प्रक्रिया केंद्रों के माध्यम से भी किसानों को बीजों का वितरण लगातार किया जा रहा है। समितियों में अतिरिक्त मांग आने पर बीज निगम द्वारा तत्काल बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही प्रक्रिया केंद्रों से भी नगद वितरण की सुविधा दी जा रही है। जिले में वर्तमान स्थिति में बीज की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और किसानों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में

बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। बीज प्रबंधक श्री टी.आर.सोनकर ने बताया कि कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने और गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों का 01 से 5 हेक्टेयर तक नि:शुल्क पंजीयन किया जा रहा है। पात्र किसान इस योजना 3,275 रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक किसान कृषि विभाग अथवा बीज प्रक्रिया केंद्र धरमपुरा में संपर्क कर नि:शुल्क पंजीयन कराते हुए योजना का लाभ ले सकते हैं।

नकली होलोग्राम और लेबल लगाकर कोचियों के जरिए से शराब की बिक्री

रायगढ़, (प्रतिदिन राजधानी)

कल पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी रायगढ़ शशि मोहन सिंह द्वारा 08 जून की रात्रि रायगढ़ पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में लंबे समय से संचालित नकली शराब के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किये जाने की जानकारी मीडिया से साझा की गई थी।

रायगढ़ पुलिस ने थाना कोतरारोड़ क्षेत्र के ग्राम धनागर में की गई सुनियोजित रेड कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में बिक्री के लिए तैयार नकली शराब - 869 नग विभिन्न पैमानों की लगभग 240 लीटर नकली शराब के साथ शराब ढक्कन, स्प्रेट के ड्रम, केटली, खाली बोतलें बरामद हुआ। जिसे आरोपी दुष्यंत उर्फ पप्पू के कब्जे से जब्त कर आरोपी गिरफ्तार किया गया था, गिरोह के अन्य सदस्य सुभाष पटेल एवं विनय ठाकुर फरार हो गए थे।

फरार आरोपियों की तलाश के दौरान

पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सुभाष चन्द्र पटेल अपने ग्राम जोरापाली स्थित फार्म हाउस में छिपा हुआ है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक शील सिंह

के अवैध कारोबार में संलिप्त था। गिरोह द्वारा फार्म हाउस में शराब का भंडारण किया जाता था तथा उसमें मिलावट कर नकली होलोग्राम एवं फर्जी लेबल लगाकर



आदित्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी सुभाष चन्द्र पटेल (50) निवासी धनागर, थाना कोतरारोड़ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि वह अपने भाई तथा सह-आरोपी विनय सिंह ठाकुर के साथ मिलकर नकली शराब

विभिन्न स्थानों पर कोचियों के माध्यम से बिक्री कराई जाती थी।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वे शराब में स्प्रेट मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाते थे और उसे खाली शराब की बोतलों में भरकर सील करते थे। नकली शराब पर फर्जी होलोग्राम एवं लेबल लगाए जाते

थे। स्प्रेट मिलाने के कारण शराब का रंग फीका पड़ जाने पर उसमें चायपत्ती का रंग मिलाकर उसे असली जैसा स्वरूप दिया जाता था।

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके फार्म हाउस से गैस सिलेंडर, सिंगल गैस चूल्हा, एल्यूमिनियम की डेराची तथा शराब तैयार करने में प्रयुक्त खाली बोतलें बरामद कर जब्त की हैं। उक्त सामग्री का उपयोग नकली शराब तैयार करने में किया जा रहा था।

आरोपी सुभाष चन्द्र पटेल को थाना कोतरारोड़ में धारा 336(4), 336(3), 340(2), 61(2), 275 बीएनएस तथा 34(2), 36, 49(क), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रकरण में शामिल अन्य फरार आरोपी विनय ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।

नवाडीहकला गांव पहुंची कलेक्टर

बलरामपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मनरेगा कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नवाडीहकला पहुंचकर मनरेगा के तहत संचालित तालाब गहरीकरण कार्य का अवलोकन किया।



होगी और इससे कृषि कार्यों की तैयारियों में सहायता मिलेगी।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अधिक संख्या में श्रमिकों को कार्य से जोड़ने तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण संबंधी परिपक्वता का निर्माण भी सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे गांवों में दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। निरीक्षण के दौरान ग्राम

पंचायत के सरपंच ने तालाब के सौंदर्यीकरण के संबंध में मौखिक प्रस्ताव भी कलेक्टर के समक्ष रखा। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक संभावनाओं का परीक्षण करने और ग्राम के हित में उचित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि तालाब गहरीकरण कार्य पूर्ण होने से क्षेत्र में जल संचयन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भू-जल स्तर सुधारने, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने तथा ग्रामीणों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा कार्यों की सतत निगरानी कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों को समय पर रोजगार एवं मजदूरी का लाभ मिले तथा विकास।

कांग्रेसियों ने मनाई विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि

लखनपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ की राजनीति के वरिष्ठ नेता स्व. विद्याचरण शुक्ल की 13वीं पुण्यतिथि 11 जून को लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विद्याचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ और देश के विकास में उनके योगदान, दूरदर्शी सोच और नेतृत्व के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह देव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सिंह देव, वीरेंद्र सिंह देव, मंडल अध्यक्ष रमेश जायसवाल, जगरोपन यादव, जिला सचिव इरशाद खान, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र जायसवाल, ब्लॉक महामंत्री मकसूद हुसैन, रामसुजान द्विवेदी, इमरान हुसैन, पार्षद बबलू मझवार, जियाउल खान, सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ज्ञात हो कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमले में घायल होने के बाद 11 जून 2013 को गुडगांव के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ था। कई लोगों ने झीरम घाटी हमले की जांच और न्याय की बात भी दोहराई। विद्याचरण शुक्ल 1957 से 2013 तक लगातार संसद में रहे, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में सूचना-प्रसारण, संसदीय कार्य और सिंचाई मंत्री रहे।

भाड़ा कटौती के विरोध में ट्रक मालिक संघ लामबंद, 15 से हड़ताल की चेतावनी

सुरजपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

लखनपुर, 11 जून। अमेरा कोयला खदान में कोयला परिवहन के लिए निर्धारित भाड़े में कटौती किए जाने के विरोध में लखनपुर ट्रक मालिक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने आरोप लगाया है कि परिवहन कंपनियों द्वारा प्रति टन भाड़े में 300 रुपये की कमी कर दी गई है, जिससे स्थानीय ट्रक संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मांगें पूरी नहीं होने पर 15 जून से खदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

गुरुवार दोपहर ट्रक मालिक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य अमेरा खदान पहुंचे और परिवहन कंपनियों तथा लिफ्टरों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व में निर्धारित भाड़ा



दरों को यथावत रखने की मांग की। संघ का कहना है कि महासमुंद के लिए 1700 रुपये प्रति टन, तिल्दा के लिए 1500 रुपये तथा रायगढ़ के लिए 1300 रुपये प्रति टन की दर से भाड़ा दिया जाता था, लेकिन हाल में इसमें 300 रुपये प्रति टन की कटौती कर दी गई है।

ट्रक मालिकों का कहना है कि डीजल, टायर, स्पेयर पार्ट्स एवं अन्य परिचालन खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा प्रत्येक चक्र में हजारों रुपये का टोल टैक्स भी देना पड़ता है। ऐसे में भाड़ा कम होने से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और

वाहन मालिकों को घाटा उठाना पड़ रहा है। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय ट्रकों को प्राथमिकता देने के बजाय अन्य राज्यों, विशेषकर नागालैंड से ट्रक बुलाकर अमेरा खदान से रायपुर, तिल्दा, रायगढ़ और महासमुंद के लिए कोयला परिवहन कराया जा रहा है। ट्रक मालिकों ने इसे स्थानीय परिवहन व्यवसायियों के हितों के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई है। ट्रक मालिक संघ के सदस्य सुरेश साहू ने आरोप लगाया कि बाहरी अर्थीकरण के ट्रकों द्वारा छत्तीसगढ़ में कोयला लोड कर परिवहन किया जा रहा है।

निर्माणाधीन नहर में अजाक्स मशीन पलटी, ऑपरेटर की दबकर मौत

बलरामपुर, (प्रतिदिन राजधानी)

बलरामपुर जिले में निर्माणाधीन पिपरील में सिंचाई परियोजना के कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। करोड़ों रुपये की लागत से बन रही नहर में कार्यरत एक अजाक्स मशीन पलट जाने से उसके ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। देर रात तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने शव को मशीन के नीचे से बाहर निकाला। बलरामपुर जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सेंदुर नदी पर नहर निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। यह परियोजना हाल ही में शुरू हुई सिंचाई योजनाओं का हिस्सा है। बुधवार शाम को टायरहाईटॉप में निर्माण कार्य के दौरान अचानक अजाक्स मशीन अनियंत्रित होकर पलट गई।



मशीन के नीचे दबने से उसके ऑपरेटर रामदयाल पंडो (निवासी ग्राम पचावल) की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंहदेव भी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने

तत्काल मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक वैभव बैकर को दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य तेज किया गया।

तातापानी चौकी प्रभारी एसआई उमेश सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद मशीन के नीचे फंसे ऑपरेटर को निकालने के लिए पहले हाइड्रॉ मशीन मंगाई गई थी, लेकिन भारी मशीन होने के कारण उससे

सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस द्वारा क्रेन को व्यवस्था कराई गई। देर रात करीब 2.30 से 3 बजे के बीच क्रेन की मदद से मशीन को हटाकर शव बाहर निकाला जा सका।

पुलिस ने गुरुवार को मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिवजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है। इस हादसे के बाद निर्माणाधीन परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी मशीनों से कार्य कराए जाने के दौरान सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

दुर्लभ वस्तु और रेडियो एक्टिव सामान बेचने का झांसा, 3 करोड़ की ठगी, 3 बंदी

अंबिकापुर, (प्रतिदिन राजधानी)

दुर्लभ पुरानी वस्तु एवं कथित रेडियोएक्टिव सामग्री की पैकिंग और बिक्री के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक ग्रामीण को झांसा देकर करीब 3 करोड़ 8 लाख 78 हजार रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुरखुर्द निवासी करमबेल कच्छप ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जुलाई 2023 से सितंबर 2024 के बीच आरोपियों ने फर्जी रिपोर्ट एवं पंजीयन दस्तावेज दिखाकर दुर्लभ पुरानी वस्तु तथा रेडियोएक्टिव सामग्री की पैकिंग और बिक्री से भारी मुनाफा होने



का लालच दिया। इस दौरान आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उससे 3 करोड़ 8 लाख 78 हजार रुपये हासिल कर लिए। शिकायत के आधार पर गांधीनगर थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में आरोपियों की तलाश के लिए साइबर सेल की सहायता से विशेष टीम गठित की गई।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीमों को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भेजा गया। इसी दौरान मुख्य आरोपी बल्ल रामा कृष्णा और संजय कुमार बिंद को बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान ठगी के आरोपों की पुष्टि होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में तीसरे आरोपी बाबूलाल राजभर को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में तेलंगाणा

निवासी डॉ. बल्ल रामा कृष्णा (51), वाराणसी निवासी संजय कुमार बिंद (38) और बाबूलाल राजभर (55) शामिल हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है तथा ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। कार्रवाई में गांधीनगर थाना पुलिस, साइबर सेल तथा रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अगले साल तक पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों से हट सकता है AFSPA: अमित शाह



आ रही आखिरी बाधा को दूर कर दिया है। इस एमओयू का मकसद असम-नगालैंड सीमा पर विवादित क्षेत्र (डीएबी) में तेल और खनिजों की खोज करना है। अधिकार-क्षेत्र से जुड़े मतभेदों के कारण इस इलाके में तीन दशकों से ज्यादा समय तक खोज का काम रुका रहा।

एमओयू को लेकर क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिर्फ एक एमओयू से रोजाना 1,000-1,500 बैरल निकालने की क्षमता को 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'सिर्फ एक ही क्षेत्र से 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का तेल निकालने की संभावना है। अगर हम नगालैंड में फैले तेल के भंडार को निकालें तो हम अपनी तेल की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर पाएंगे।'

पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'दशकों पुरानी नक्सलवाद, आतंकवाद और धारा 370 आदि की समस्या को 12 वर्षों में हमारी सरकार ने समाप्त किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज crisis management का वैश्विक मॉडल बनकर उभरा है, जिसका विश्वभर में शोध हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज NDA 80% भूभाग और 76% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए सुशासन और विकास की राजनीति को आगे बढ़ा रहा है।'

शांति की राह पर पूर्वोत्तर

उन्होंने कहा, 'मुझे भरोसा है कि एक-दो राज्यों को छोड़कर, हम अगले साल पूरे पूर्वोत्तर से अफस्य हटा देंगे।' इस एमओयू पर हस्ताक्षर को एक ऐतिहासिक पल बताते हुए अमित शाह ने कहा कि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित पूर्वोत्तर के लक्ष्य में

जयशंकर ने यूरोप को दिखाया आईना बोले- आपके हथियारों से भारत पर हमले होते हैं



पर सवाल उठाने पर जयशंकर ने कहा, 'यहाँ एक बात साफ कर दो। आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला

हितों से समझौता नहीं करेगा भारत

बता दें कि पश्चिमी देश और अमेरिका कई बार भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने की आलोचना कर चुके हैं। उनका आरोप है कि भारत रूस के मुनाफे में सहयोग कर युद्ध की फंडिंग कर रहा है। अमेरिका ने पिछले साल इस तरह के आरोप लगाते

हुए भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया था। हालांकि भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि भारत अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा।

नहीं हुआ है। काश, मैं यही बात भारत के संदर्भ में यूरोप के हथियारों को लेकर कह पाता।"

उन्होंने आगे कहा, "सच यह है कि यूरोप ऐसे देशों को हथियार बेचता है, जिनका इस्तेमाल भारत पर हमलों के लिए किया जाता है। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ऐसा ही रहा है। हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई काम नहीं किया, इसलिए मेरा यह कहना पूरी तरह

तर्कसंगत है।

भारत को तलाशने पड़े विकल्प

वहीं रूसी तेल खरीदने के भारत के रुख पर जयशंकर ने बताया कि कैसे यूरोपीय देशों के फैसलों ने ही भारत को यह कदम उठाने पर मजबूर किया था। उन्होंने बताया, 'रहम तेल की कीमत और उपलब्धता के आधार पर खरीदारी करते हैं। उस समय बाजार में जो तेल उपलब्ध था, वह रूस का ही

भारत ने 12 परमाणु हथियार किए तैनात, पाकिस्तान ने जताई चिंता

नई दिल्ली। दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन और सैन्य ताकत को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। वैश्विक हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने इतिहास में पहली बार अपने परमाणु हथियारों को केवल स्टॉकपाइल में रखने के बजाय सीधे तौर पर ऑपरेशनल मोड में तैनात कर दिया है।



इस खुलासे के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार और वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से बेहद डरा हुआ बयान सामने आया है, जिसमें इस्लामाबाद ने खुले तौर पर माना है कि भारत की परमाणु ताकत अंतरराष्ट्रीय अनुमानों से कहीं ज्यादा बड़ी और घातक हो सकती है।

पाकिस्तान ने भारत की परमाणु-सक्षम पनडुब्बियों के जरिए समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के विस्तार और लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक



मिसाइल (ICBM) प्रणालियों के विकास को अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। पहली बार 'डिप्लॉयड मोड' में आए भारतीय न्यूक्लियर वॉरहेड रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास वर्तमान में लगभग 190 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 190



वॉरहेड्स में से 12 को 'ऑपरेशनल रूप से तैनात' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह पहली बार है जब किसी वैश्विक रक्षा एजेंसी ने भारत के परमाणु हथियारों के एक हिस्से को केवल भंडार के रूप में न देखकर, पूरी तरह से सक्रिय सैन्य तैनाती के रूप में दर्ज किया है। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों से परमाणु हमला करने की भारत

भारत की परमाणु ट्रायड और 'कैनिस्ट्राइजेशन' तकनीक से सहमा इस्लामाबाद

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी कर सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वे नई दिल्ली की तेजी से बढ़ती रणनीतिक क्षमताओं और बदलते परमाणु रुख पर बहुत बारीक नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान ने विशेष रूप से भारत की मिसाइल प्रणालियों के कैनिस्ट्राइजेशन को

लेकर गहरी चिंता जताई है। कैनिस्ट्राइजेशन ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें परमाणु वॉरहेड को पहले से ही मिसाइल के अंदर सील करके रखा जाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में मिसाइल को बहुत कम समय में और बेहद तेजी से दागा जा सकता है।

एआई-171 हादसे की बरसी पर एएआईबी ने जताई संवेदना

अहमदाबाद। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 हादसे की बरसी पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एएआईबी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और 12 जून 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।



और मानवीय पहलुओं की गहन जांच की है। विमान प्रणालियों, उड़ान रिकॉर्डर डेटा, इंजन घटकों, रखरखाव और परिचालन अभिलेखों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

एएआईबी ने बताया कि हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच नियम, 2017 और आईसीएओ अनुलनक 13 के मानकों के अनुसार की जा रही है। प्राथमिक रिपोर्ट 12 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। जांच दल ने पिछले एक वर्ष में तकनीकी, परिचालन, संगठनात्मक

एएआईबी ने कहा कि एकत्र साक्ष्यों का व्यापक विश्लेषण जारी है। अंतिम रिपोर्ट सभी जांच गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी। ब्यूरो ने मीडिया और आम जनता से जांच पूरी होने तक अटकलों से बचने की अपील की है।



टीवी-रेडियो नियमों का मसौदा जारी, 27 जुलाई तक मांगे सुझाव

पुराने दिशानिर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम के तहत एक नियमावली में समाहित करने की है तैयारी

किया गया है। नियम लागू होने के बाद प्रसारण सेवाओं से जुड़े मौजूदा अलग-अलग दिशानिर्देशों का स्थान ये नियम ले लेंगे। इससे उद्योग को एक सरल और एकीकृत नियमावली मिलेगी। मसौदे में प्राथिकरण प्रक्रिया के डिजिटल कार्यान्वयन, सरल प्रक्रिया, कई दिशानिर्देशों की जगह एक नियामक प्रारूप और अनुमति समझौते पर हस्ताक्षर की आवश्यकता हटाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मसौदा नियमों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए प्रकाशित किया है। सुझाव, टिप्पणी या इनपुट 27 जुलाई 2026 तक ईमेल के माध्यम से अवर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं।

अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर शाह ने की समीक्षा, बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के दिए निर्देश



3 जुलाई से 28 अगस्त तक होगी यात्रा, झोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहायक मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की सुरक्षा तैयारी को लेकर नई दिल्ली में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई से 28

अगस्त 2026 तक आयोजित होगी। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, थलसेना प्रमुख, आईबी निदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक, CAPF के महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने निर्देश दिए

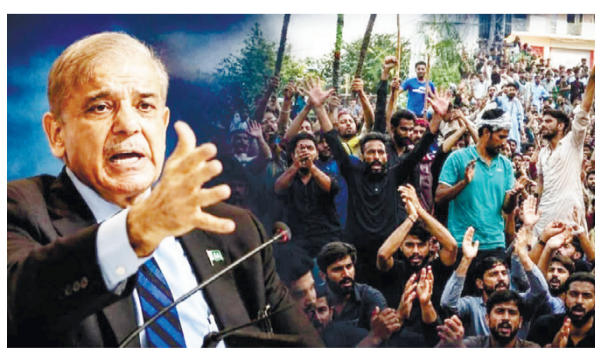
कि यात्रा मार्ग पर जम्मू-कश्मीर पुलिस, CAPFs और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड स्थापित करें। सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन, सीसीटीवी, सर्विलांस सिस्टम और आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाए।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के पंजीकरण, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन की सुविधा व्यवस्था हो। मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान के आधार पर ही श्रद्धालुओं के जत्थों को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों और पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र जारी होंगे और पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाए जाएंगे।

कंगाली की कगार पर पाकिस्तान! शिक्षा बजट में कटौती, गरीबी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। गुरुवार को जारी 'पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26' के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। देश में जहां एक तरफ गरीबी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बच्चों की शिक्षा के बजट में भारी कटौती कर दी है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, पाकिस्तान में राष्ट्रीय गरीबी दर बढ़कर 28.9% हो गई है, जबकि शिक्षा पर होने वाला खर्च घटकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का महज 0.8% रह गया है। सचिवों ने कहा गया है कि बढ़ती

महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 2018-19 में प्रति व्यक्ति मासिक गरीबी रखा 3,757 रुपये थी, जो अब बढ़कर 8,484 रुपये हो गई है। ग्रामीण इलाकों में आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। ग्रामीण गरीबी 28.2 प्रतिशत से बढ़कर 36.2 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी 11 प्रतिशत से बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई। प्रांतों की बात करें तो बलूचिस्तान सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है, जहां 47 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 35.3 प्रतिशत, सिंध में 32.6 प्रतिशत और पंजाब में 23.3



प्रतिशत लोग गरीब हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आय असमानता लगातार बढ़ रही है। गिनी गुणांक 28.4 से बढ़कर 32.7 हो गया है, जो अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को दर्शाता है। आर्थिक सर्वे ने चेतावनी दी है

कि मिडिल इस्ट में जारी तनाव और भू-राजनीतिक संकट पाकिस्तान की स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को मिलने वाली लगभग 55 प्रतिशत विदेशी मुद्रा (रिमेंटेंस) मिडिल इस्ट से आती है। यदि वहां हालात

बिगड़ते हैं तो लाखों परिवारों की आय प्रभावित हो सकती है और गरीबी और बढ़ सकती है।

शिक्षा क्षेत्र में स्थिति बेहद चिंताजनक

शिक्षा क्षेत्र की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बताई गई है। वित्त वर्ष 2025 में शिक्षा पर सरकारी खर्च घटकर 962 अरब पाकिस्तानी रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष 1,251 अरब रुपये था। शिक्षा पर कुल खर्च अब देश की जीडीपी का सिर्फ 0.8 प्रतिशत रह गया है, जबकि 2023 में यह 1.5 प्रतिशत था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शिक्षा बजट में भारी कटौती दर्ज की गई, हालांकि सिंध और बलूचिस्तान

ने खर्च बढ़ाया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में साक्षरता दर 63 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता केवल 54 प्रतिशत है। देश में अभी भी लगभग एक-तिहाई बच्चे स्कूल से बाहर हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी है। पूरे देश में केवल 59 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में बिजली उपलब्ध है, जबकि बलूचिस्तान में यह आंकड़ा महज 21 प्रतिशत है। आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर निवेश नहीं बढ़ाया गया तो पाकिस्तान में गरीबी, असमानता और बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हो सकती है।

रायपुर में नशे पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा

फिल्में समाज को संदेश देने का सशक्त माध्यम : राज्यपाल डेका

रायपुर (प्रतिदिन राजधानी)

फिल्में और डॉक्यूमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक संदेश देने का एक प्रभावी साधन हैं। राज्यपाल श्री रमन डेका ने आज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में उक्त बातें कही। यह कार्यक्रम रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

राज्यपाल ने कहा कि आदिम युग से ही मनुष्य विभिन्न माध्यमों से अपने विचार और संदेश व्यक्त करता रहा है। समय के साथ नाटक, रेडियो, टेलीविजन और अब डिजिटल माध्यमों ने इस भूमिका को और व्यापक बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले सिनेमा का मूल उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि समाज को संदेश देना और जागरूक करना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध उल्लेखनीय सफलता मिली है। फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि अब



वे बस्तर की समृद्ध संस्कृति से देश और दुनिया को परिचित कराएं। इससे क्षेत्र की सकारात्मक छवि को मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल ने सद्गति, चरणदास चोर और देवदास जैसी फिल्मों और नाटकों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जागरूकता लाने वाली फिल्मों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और पर्व-त्योहारों जैसे हमारे धरोहर को स्थायी रूप से संरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। उन्होंने कलाकारों से लोककला, लोकगीत, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि मोबाइल की बढ़ती लत आज गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। बच्चे खेल के मैदानों से दूर हो रहे हैं और उनकी रचनात्मकता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कलाकारों से आग्रह किया कि वे नई पीढ़ी को कला, संगीत, नाटक और नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आगे आए। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री फिल्मों छत्तीसगढ़ के भीम दाऊ चिताराम, हैप्पी बर्थडे और स्क्रीन के निर्माता-निर्देशकों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में स्वागत उद्घोषण संस्कृति विभाग के संचालक श्री संजय कन्नोजे ने दिया। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल्स रायपुर में राष्ट्रीय ऑन्कोलॉजी शिखर सम्मेलन 'ऑन्कोस्फीयर 2.0' का आयोजन करेगा

देशभर के 300 से अधिक अग्रणी ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं शोधकर्ता होंगे शामिल

दो दिवसीय अकादमिक सम्मेलन में प्रिसिजन मेडिसिन, इम्यूनोथेरेपी और कैंसर उपचार की अगली पीढ़ी की तकनीकों पर होगी विस्तृत चर्चा

रायपुर (प्रतिदिन राजधानी)

मध्य भारत के अग्रणी स्वास्थ्य संस्थानों में से एक, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल्स, रायपुर, अपने प्रमुख शैक्षणिक ऑन्कोलॉजी सम्मेलन 'ऑन्कोस्फीयर 2.0' का आयोजन 13 और 14 जून 2026 को होटल बैबिलोन इंटरनेशनल, रायपुर में करेगा। यह सम्मेलन देशभर से प्रमुख ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों को एक मंच पर लाएगा, जहाँ कैंसर देखभाल के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवाचारों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भारत के प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ भाग लेंगे, जो उभरती उपचार पद्धतियों, जटिल क्लिनिकल मामलों और कैंसर के निदान एवं उपचार को पुनर्निर्माणित करने वाले महत्वपूर्ण नवाचारों पर विचार-विमर्श करेंगे।

कैंसर देखभाल में प्रगति केवल चिकित्सा उपलब्धियों से नहीं, बल्कि ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव के निरंतर आदान-प्रदान से भी संभव होती है। अपने प्रमुख शैक्षणिक पहल 'ऑन्कोस्फीयर 2.0' के माध्यम से, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल्स विशेषज्ञों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देने, बहु-विषयक सहयोग को प्रोत्साहित करने और कैंसर उपचार के मामलों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

दो दिवसीय सम्मेलन में वैज्ञानिक सत्र, मुख्य व्याख्यान, बहु-विषयक पैनल चर्चाएँ और केस-आधारित शिक्षण शामिल होंगे। इनमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजिकल मैलिनैंसी, प्रिसिजन मेडिसिन, इम्यूनोथेरेपी और रोगी-केंद्रित कैंसर देखभाल जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह आयोजन सर्वोत्तम



प्रथाओं के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे रोगियों के परिणामों में सुधार हो सके।

सम्मेलन से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए, डॉ. संदीप दवे, प्रबंध निदेशक एवं क्लिनिकल डायरेक्टर, रामकृष्ण हृदय अस्पताल, के साथ डॉ. रवि जायसवाल (वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट), डॉ. मौर्य (वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट), डॉ. नवीन जैन (वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट), डॉ. गौरव गुप्ता (वरिष्ठ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट) और डॉ. नीरू केरकेर (वरिष्ठ सलाहकार - न्यूक्लियर मेडिसिन) उपस्थित थे।

डॉ. संदीप दवे ने कहा, भारत में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो चिकित्सा विज्ञान, तकनीक और व्यक्तिगत उपचार पद्धतियों में प्रगति के कारण संभव हुआ है। साथ ही, बढ़ते कैंसर भार के चलते निरंतर सीखने, सहयोग और बहु-विषयक उपचार की आवश्यकता भी बढ़ रही है।

'ऑन्कोस्फीयर 2.0' देश के अग्रणी ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है, जहाँ वे क्लिनिकल अनुभव साझा कर सकते हैं, नवाचारों पर चर्चा कर सकते हैं और कैंसर उपचार के मानकों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे शैक्षणिक मंच यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि ज्ञान का सही उपयोग मरीजों के बेहतर परिणामों में हो।

डॉ. रवि जायसवाल ने कहा, ऑन्कोलॉजी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। प्रिसिजन मेडिसिन, इम्यूनोथेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और टार्गेटेड थेरेपी में प्रगति ने कैंसर के निदान और उपचार की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। 'ऑन्कोस्फीयर 2.0' चिकित्सकों और विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा, जहाँ वे जटिल क्लिनिकल मामलों पर चर्चा कर सकेंगे और नए उपचार तरीकों से अपडेट रह सकेंगे, जिससे मरीजों के परिणाम बेहतर होंगे।

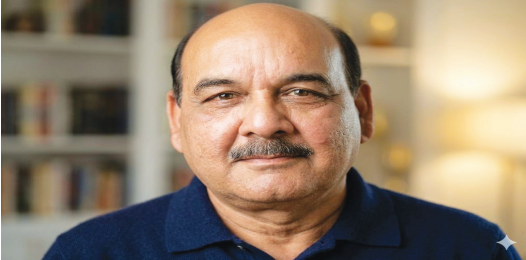
विशेषज्ञों ने बताया कि 'ऑन्कोस्फीयर 2.0' स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ज्ञान साझा करने, चुनौतीपूर्ण क्लिनिकल मामलों पर चर्चा करने और कैंसर निदान एवं उपचार के भविष्य को आकार देने वाले नवाचारों का पता लगाने के लिए एक अनूठे मंच साबित होगा।

इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों से ऑन्कोलॉजिस्ट, चिकित्सक, सर्जन, रेडिएशन विशेषज्ञ, स्वास्थ्य पेशेवर और स्नातकोत्तर छात्र बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है।

अरविन्द जैन दिगम्बर जैन समाज की मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की संस्था श्री नागपुर प्रांतीय दिगम्बर जैन खंडेलवाल सभा के प्रांतीय मंत्री बने

रायपुर (प्रतिदिन राजधानी)

छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रमुख सलाहकार अरविन्द जैन जैन समाज की संस्था श्री नागपुर प्रांतीय दिगम्बर जैन खंडेलवाल सभा



के मंत्री पद पर मनोनीत हुए। अध्यक्ष मनोज पहाड़िया ने इनकी कुशल कार्यशैली व मनु व्यवहार व अनुभव को ध्यान में रखकर उन्हें मंत्री पद पर मनोनीत किया, निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में समाज लाभान्वित होगा।

मोदी और मैक्रों 14 जून को फ्रांस में करेंगे 'भारत इनोवेट्स' का उद्घाटन



एजेंसी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 14 जून को फ्रांस के नीस में 'भारत इनोवेट्स 2026' का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य भारत के डीप-टेक स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान क्षमता को वैश्विक निवेशकों तथा उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत करना है।

शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कार्यक्रम में भारत के 120 नवप्रवर्तक, 15 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान, 500 से अधिक निवेशक, प्रमुख कॉरपोरेट कंपनियाँ, वेंचर कैपिटल फर्म, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और उद्योग जगत के नेता भाग लेंगे। इसमें एडवॉन्स कंफ्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद भी उपस्थित रहेंगे।

मंत्रालय के अनुसार भारत इनोवेट्स 2026 का पहला संस्करण भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप और नवाचारों को वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत से जोड़ने का मंच बनेगा। कार्यक्रम के दौरान डीप-टेक, अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप विस्तार और सीमा-पार निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सहयोगी समझौतों और घोषणाओं की

छग में 16 जून से मनेगा शाला प्रवेश उत्सव 2026, तिलक लगाकर बच्चों का होगा स्वागत

रायपुर (प्रतिदिन राजधानी)

छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण माहौल तैयार करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (हृदय 2020) के अनुरूप, प्रदेशभर में 16 जून 2026 से शाला प्रवेश उत्सव 2026 का गरिमामय आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रतीत सिंह ने मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्रवेश उत्सव को एक उत्सव का रूप देने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके तहत गांवों और शहरी वार्डों में मुनादी कराई जाएगी। बैनर-पोस्टर और रैलियों के जरिए जागरूकता



बढ़ाई जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शाला विकास समितियों और पालकों (अभिभावकों) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल खुलने से पहले भवनों, परिसरों और कक्षाओं की पूरी साफ-सफाई और आवश्यक मरम्मत कर ली जाए। मरम्मत योग्य भवनों का काम 15 जून 2026 तक हर हाल में पूरा करने को कहा गया है ताकि बच्चों को एक आकर्षक और प्रिंट-रिच (शैक्षणिक चित्रों और

दीवारों पर लिखी जानकारियों से लैस) वातावरण मिल सके।

प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया है। कक्षा पहली में आगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों की सूची प्राप्त कर सीधे स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा छठवीं में प्राथमिक शालाओं से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण छात्रों की सूची और टीसी (स्थानांतरण प्रमाण-पत्र) लेकर कक्षा 6वीं में उनका दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। शाला त्यागी बच्चे, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें दृढ़कर दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा, स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनविश्वास से परिपूर्ण 4399 दिनों की निरंतर राष्ट्रसेवा का कीर्तिमान



रायपुर (प्रतिदिन राजधानी)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का गौरव प्राप्त किया है, इन 12 वर्षों में देश ने गरीब कल्याण से लेकर डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी तक सभी क्षेत्रों में तेज विकास देखा है।

राष्ट्रसेवा के प्रति उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज इस शुभ अवसर पर आकाशवाणी चौक स्थित काली माता मंदिर में हवन-पूजन किया तथा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इसी प्रकार भारत को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाते रहें ऐसी प्रार्थना कर हवन पूजन का आयोजन भाजपा सिविल लाइन मंडल स्थित माँ काली माता मंदिर परिसर में पंचमुखी हनुमान मंदिर, आकाशवाणी के सामने सम्पन्न हुआ, जिसमें मंत्री राम विचार नेताम, विधायक सुनील सोनी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंध, जिला कोषाध्यक्ष पन्ना दुबे, सीमा साहू, मंडल प्रभारी सुभाष तिवारी, शंभू शर्मा, अध्यक्ष सुनील कुमार कुकरेजा, शैलेन्द्र सिंह सोमवंशी, पार्षद अमर

गिदवानी, सचिन मेघानी, संतोष सीमा साहू, मुरली शर्मा जी, स्वप्निल मिश्रा, तेज कुमार बजाज, बसला होतवानी, कचरू साहू, मित्र सेन धीमान, दक्षिण विधानसभा मंडलो के अध्यक्ष, सचिन सिंघल, संतोष सोनी, अभिषेक तिवारी, केदार धनगर, प्रकाश जोशी, रितेश वाधवा, धनेश मल्लानी, कमल रंधावा, अनीता बोए, सुमन मुधा, मैरी फ्रंसीस, सीमा साहू, शुभम लवी ठाकुर, विशाल पटेल, अंकित निमाणी, अनुराग जैन, आशा अरोरा, गौरी महानंद, अमन मराठी, शिववर्णन सगरवंशी, कार्यकर्तागण सहित विधानसभा के गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल आयोग का बड़ा एक्शन... डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में बाल श्रम पर बड़ी कार्रवाई

जोखिमपूर्ण फैक्ट्री से 9 नाबालिग मुक्त, कुल 20 बच्चों को संरक्षण

दूसरे प्रदेशों के नाबालिगों का रेस्क्यू, बाल तस्करी के एंगल से होगी जांच

रायपुर (प्रतिदिन राजधानी)

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में बच्चों के संरक्षण हेतु प्रदेशभर में विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र से 9 नाबालिग बच्चों, बिलासपुर में आरपीएफ के माध्यम से 7 बच्चों तथा रायपुर जीआरपी के माध्यम से 4 बच्चों का रेस्क्यू कर कुल 20 बच्चों को संरक्षण में लिया गया। इसी क्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के उरला स्थित मारुति नंदन स्टील इंडस्ट्रीज में विशेष औचक छापाकार कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया



गया कि लोहे की फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से गंभीर एवं जोखिमपूर्ण प्रकृति का कार्य कराया जा रहा था। मौके से 9 बच्चों को तत्काल संरक्षण में लेकर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया तथा उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि रेस्क्यू किए गए बच्चे ओडिशा, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निवासी हैं।

बच्चों ने बताया कि उन्हें एक ठेकेदार के माध्यम से रायपुर लाया गया था, जो बिहार का रहने वाला है। मामले में संबंधित ठेकेदार, बच्चों को यहां लाने वाले अन्य व्यक्तियों तथा संभावित बाल तस्करी के पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। बच्चों के परिजनों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया बच्चों के साथ क्रूरता, शोषण एवं अवैध रूप से जोखिमपूर्ण कार्य कराए जाने के

तथ्य सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, 79 एवं 143 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बाल श्रम एवं संभावित बाल तस्करी से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं की भी विस्तृत जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि, बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का गंभीर

उल्लंघन है, विशेषकर तब जब उनसे जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कराया जाता है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है। बाल श्रम एवं बाल तस्करी जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध आयोग पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध विधिबद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी संजय निराला, विपिन ठाकुर, श्रम विभाग की टीम एवं संबंधित अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति रही। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को आवश्यक संरक्षण, परामर्श, चिकित्सकीय सहायता एवं पुनर्वास की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।